सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 258, नई दिल्ली । गुरुवार, 28 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया, वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 दिल्ली को रानी खेड़ा इलाके में मिलेगा 147 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र
06 बचपन, परिवार और अनुभवों से सबक
08 धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए मारकाट कब थमेगी?

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बड़ा फैसला :- दिल्ली में पीसीआर वैन और लोकल पुलिस भी करेगी चालान

क्या दिल्ली के प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की जनता को गुनाहगार मानती हैं?

संजय बाटला

नई दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण के खिलाफ सरकार की नाकामी की सजा दिल्ली की जनता पहले से ही भुक्त रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जनता के खिलाफ एक और हथियार दिया दिल्ली पुलिस के हाथ।

अब दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन (प्रखर) और स्थानीय थाना पुलिस भी ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान करेंगी।

दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन (प्रखर) और स्थानीय थाना पुलिस भी ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान करेंगी।

पीसीआर वैन में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और स्थानीय थाना पुलिस को एक या दो चालान मशीनें दी गई हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सुप्रीम फटकार के बाद सभी 15 जिला कप्तानों व उनसे सीनियर पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त आदेश दिए। साथ ही कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सांस नहीं तो वोट नहीं: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक मार्च

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड

नईदिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। ₹सांस नहीं तो वोट नहीं₹ के नारे के साथ लोगों ने संसद भवन के पास शांतिपूर्ण मार्च निकालकर सरकार से ठोस नीतियों की मांग की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

प्रदूषण के खिलाफ यह अनोखा मार्च प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से शुरू होकर संसद भवन के पास तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में 'सांस नहीं तो वोट नहीं₹ और ₹साफ हवा मेरा अधिकार' जैसे नारों वाले पोस्टर और बैनर थाम रखे थे। खास बात यह थी कि कुछ लोग सांकेतिक ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर आए, जो प्रदूषण की गंभीरता को दर्शा रहे थे।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के गोलचक्कर से पहले ही रोक लिया, लेकिन इसका जज्बा कम नहीं हुआ। प्रदर्शन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर वर्ग के लोग शामिल थे। उनका कहना था कि प्रदूषित हवा सबसे ज्यादा बाहर काम करने वाले और बच्चों को प्रभावित करती है।

नोएडा से आए प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य देना चाहते हैं। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भविष्य में हमें ऑक्सीजन सिलिंडर खरीदने की जरूरत पड़ सकती है।"

पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने इसे सरकार और नीति निर्माताओं के लिए एक कड़ी चेतावनी करार दिया। उन्होंने कहा, **'बच्चे इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है।'**

युवा हल्ला बोल से जुड़ी राशिदा ने कहा, **'पानी और हवा तो हर इंसान का न्यूनतम अधिकार है। लेकिन आज इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।'**

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि साफ हवा और पानी को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी आरोप-प्रत्यारोप से बचें और जमीन पर काम करें। इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए ताकि जनता को साफ हवा का अधिकार मिल सके।

यह प्रदर्शन सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सवाल है सरकार से। क्या हम अपने बच्चों को स्वच्छ हवा और पानी का भविष्य दे पाएंगे? या फिर आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलिंडर हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन जाएंगे?

साफ हवा और पानी की लड़ाई अब सिर्फ पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्या सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी? और क्या वाकई ठोस नीति बनाई जाएगी? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मुद्दे पर अपडेट देते रहेंगे।

दिल्ली एनसीआर के टैक्सी-बस और टेम्पो ट्रेवलर के मालिक, दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में CAQM और दिल्ली सरकार के खिलाफ भारी धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार के प्रदूषण के नाम पर दोहरा रवैया और भेदभाव करने के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के टैक्सी-बस और टेम्पो ट्रेवलर के मालिक, दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में CAQM और दिल्ली सरकार के खिलाफ 12 बजे 28 नवम्बर को जंतर मंतर पर भारी धरना प्रदर्शन करने जा रहें हैं.

यें प्रदर्शन प्रदूषण की आड़ में डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रैवेलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर ना चलने देने के और उन गाड़ियों पर 20 हजार जुर्माने के खिलाफ हैं

ट्रांसपोर्टर्स की मुख्य मांगे :-

1:- डीजल BS 3 और 4 टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) को रोड पर चलने की इज्जाजत तूरंत दी जाए.

2:- डीजल BS 3/4 बसों टैक्सी और टेम्पो ट्रेवलर (LMV 4 पहिये) ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर के ग्रेप स्टेज से हमेशा के लिए बाहर किया जाए.

3:- 15 नवम्बर 2024 के बाद हमारी जितनी टूरिस्ट टैक्सी बसों और टेम्पो ट्रैवेलर के चालान हुए हैं वो सारे चालान केन्सिल किये जाए.

4:- प्रदूषण कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी और फैक्ट्रीयों के धूयें से होता हैं, इनको कंट्रोल किया जाए.

5:- कृत्रिम बारिश कराई जाये

6:- दिल्ली के ऊपर उड़ने वाले जहाजो को बंद किया जाए.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की कमिसन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट को आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल BS 4टैक्सी -बसों और टेम्पो ट्रेवलर को चलने की इज्जाजत देनी चाहिए बल्कि इन गाड़ियों को ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर से ग्रेपसिस्टम से हमेशा बाहर भी रखना चाहिए. क्योंकि यें देशी विदेशी पर्यटको को दिल्ली से बाहर घुमाने ले जाती हैं और 5- 10 दिन बाद दिल्ली में लौटती हैं, दिल्ली में डीजल की नार्मल गाड़ियों को सन 2000 में बंद कर दिया गया था उसके बाद भारत स्टेज 2 गाड़ियाँ आई उस वक़्त कहा गया की ये प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं कुछ साल बाद BS 3/4 गाड़ियाँ आईं ये भी प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं जिन्हे प्रदूषण के नाम पर बंद किया जा रहा हैं.

संजय सम्राट का कहना हैं की इन गाड़ियों की हर महीने भारी भरकम किस्तें देनी पडती हैं.

साथ ही इन्शुरन्स, रोड टैक्स, स्टेट टैक्स और ड्राइवर की तनख्वा अगर इन गाड़ियों को चलने से रोका जाता हैं तो क्या सरकार या CAQM इन गाड़ियों की किश्ते देगा या ड्राइवर की तनख्वा देंगे???

सरकार या CAQM ने आसमान के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाजो के उम्र की बात करी या कभी चेक किया की ये आसमान में कितना धुआं देते हैं???

सरकार और CAQM या इनसे जुडी संशथाये गरीब टैक्सी बस वालो को ही टारगेट करती हैं.

यें करोडो लोगों की रोजी रोटी का सवाल हैं. दिल्ली सरकार और CAQM प्रदूषण की आड़ में BS 6 डीजल गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिकवाने का काम कर रहें हैं ऐसी पूरी संभावना हमें लग रही हैं?

क्योंकि BS 6 डीजल गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलने की इज्जाजत इन्होने दी हुई हैं क्योंकि इन्हे लगता हैं की यें गाड़ियाँ ऑक्सीजन दें रही हैं?

CAQM और दिल्ली सरकार के तुगलकी फरमान से दिल्ली एनसीआर के लोग हीं नहीं पूरे भारत के लोग परेशान हैं जो दिल्ली में BS 4 डीजल प्राइवेट कारे और BS 3 पेट्रोल कारे लेकर आ रहें हैं उनसे 20 हजार रुपए चालान के नाम लिए जा रहें हैं, इतना जुर्माना तो विदेशी शासको ने भी कभी भारत की जनता पर नहीं लगाया जितना दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी सिंह जी और पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने लगवाया.

यें भारी जुर्माना इसलिए लगाया हैं जिससे लोग BS 6 या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर मजबूर हो जाए?

2015 में बना फ्लाईओवर खस्ताहाल, जबकि 1980 के अभी तक चल रहे... दिल्ली HC ने CBI जांच करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2015 में बने एक खस्ताहाल फ्लाईओवर के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारियों की खिंचाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की जा रही है। 1980 के दशक में बने फ्लाईओवर आज भी काम कर रहे हैं जबकि 2015 में बना फ्लाईओवर जर्जर हालत में है।

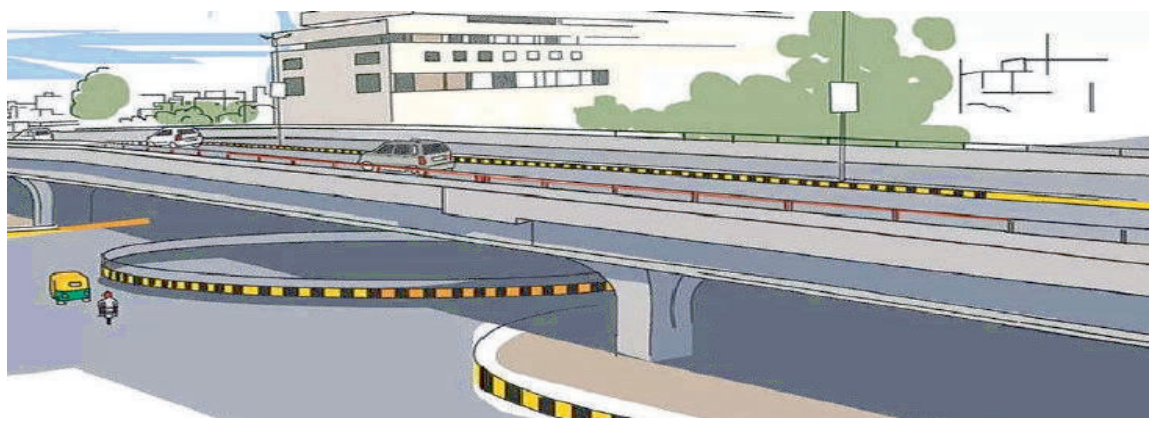

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नत्थू कॉलोनी चौक के पास बने फ्लाईओवर की खराब स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की खिंचाई कर दी। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कमजोर संरचना के बावजूद मामले में न तो कोई आंतरिक जांच हुई और न ही किसी को इस बात की परेशानी थी कि फ्लाईओवर पर रिपोर्ट 2021 से ही प्रतीक्षित है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहा था।

घोटाले में कौन हैं शामिल?

पीठ ने कहा वर्ष 2015 के इस घोटाले में कौन लोग शामिल हैं? हमें बताएं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि सीबीआई इस कृत्य के पीछे के लोगों का पता लगाएगी।

1980 में बने फ्लाईओवर आज भी काम कर रहे

पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता से कहा कि भला फ्लाईओवर की संरचना इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? यह 10 साल भी पुरानी नहीं है। अदालत ने अधिवक्ता से पूछा कि क्या इस तरह का फ्लाईओवर, जिस पर आपने करोड़ों खर्च किए होंगे, गिर सकता है? पीठ ने कहा कि वर्ष 1980 के दशक में बनाए गए सभी फ्लाईओवर आज भी काम कर रहे हैं और 2015 में आपका निर्माण खस्ताहाल है।

कोर्ट ने व्यक्त की चिंता

पीठ ने कहा कि आपको इस मामले में कुछ जांच का आदेश देना होगा। पीठ ने फ्लाईओवर के गिरने की स्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की और संरचना (निर्माण) में दोष सामने आने के बाद अधिकारियों से कदम उठाने के लिए कहा।

क्या फ्लाईओवर साइकिल के लिए हैं?

पीठ ने दिल्ली सरकारी की खिंचाई करते हुए कहा कि आपका समाधान यह है कि भारी यातायात की अनुमति नहीं है। फिर यह फ्लाईओवर किस लिए है, साइकिल के लिए। पीठ ने कहा कि आप इस तरह का दोषपूर्ण निर्माण नहीं कर सकते। अदालत ने अधिवक्ता से पूछा कि आपको किसने पूर्णता प्रमाण पत्र दिया? अब तक कोई आंतरिक जांच नहीं हुई। आपने साक्ष्यों को नष्ट होने दिया।

3 दिसंबर को होगी सुनवाई

वहीं, दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि पीडब्ल्यूडी व पर्यटन और परिवहन विकास निगम (टीटीडीसी) के बीच का जो विवाद था वो सुलझ गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर के लिए तय की है।

अदालत भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार और उसके पीडब्ल्यूडी और पर्यटन और परिवहन विकास निगम (टीटीडीसी) को नत्थू कॉलोनी चौक के पास फ्लाईओवर की मरम्मत और उसे फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

ओवरस्पीडिंग...80 किमी प्रति घंटा की गति वाले रोड पर 130 की गति से दौड़ रहे वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

देहरादून : राजधानी में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चालाय जा रहा है। परिवहन विभाग की टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में चेकिंग अभियान चलाकर ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने 190 वाहनों के चालान काटे हैं।

राजधानी में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान चालाय जा रहा है। मंगलवार को विभाग की ओर से ओवरस्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान टीम ने 190 वाहनों के चालान किए हैं।

देहरादून संभाग के आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि टीम ने आईएसबीटी, जीएमएस रोड, पटेल नगर और सहारनपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों के चालान काटे हैं। इस दौरान तय से 50 किमी प्रति घंटा अधिक गति से दौड़ रही एक कार का चालान किया गया है।

इन वाहन के स्वामियों को परिवहन विभाग के कार्यालय में भी बुलाया जाएगा। इस दौरान उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। चेकिंग के लिए चार टीमों को लगाया गया था। इसमें एआरटीओ राजेंद्र विराटिया, स्वेता रौथाड़, अनुराधा पंत और एमडी पपनै आदि मौजूद रहे।

सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट है जैसलमेर, इन 5 जगहों की खूबसूरती देख आप भी हो जाएंगे राजस्थान के

सर्दी का मौसम आते ही घूमने का मन करने लगता है। ऐसे में अगर आप भी इस सीजन राजस्थान में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जैसलमेर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। राजस्थान की इस Golden City में मौसम बेहद सुहावना होता है और खास बात है कि अपने बजट का ध्यान रखते हुए आप यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए जानें कैसे।

नई दिल्ली। चारों ओर फैले सुनहरे रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर (Golden City of India), अपनी पीली बलुआ पत्थर की इमारतों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। दूर से देखने पर यह शहर सुनहरे रेत के सागर में एक चमकदार मोती की तरह लगता है। Jaisalmer के लोग भी अपनी खास पहचान रखते हैं। बड़ी-बड़ी मूंछों और रंग-बिरंगी पगड़ियों वाले पुरुष और सितारे और शीशे लगे लहंगे पहनने वाली महिलाएं इस शहर की शान बढ़ाती हैं। पीले बलुआ पत्थर से बनी जाली और झरोखों वाली वास्तुकला, चमड़े की जूतियों की दुकानें, ब्लॉक प्रिंट वाले स्कार्फ और छोटी-छोटी कलाकृतियों से सजे बाजार आपको पुराने जमाने में ले जाएंगे। ऐसे में, आइए आपको बताते हैं कि सर्दियों में यहां घूमने के लिए आप किन-किन जगहों (Best Places To Visit In Jaisalmer) पर विजिट कर सकते हैं।

जैसलमेर का किला

थार के सुनहरे रेगिस्तान में टिका, जैसलमेर का किला एक सुनहरे महल की तरह चमकता है। राजस्थानी वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना, भारत का सबसे बड़ा जीवित किला है, जहां लगभग 5000 लोग आज भी निवास करते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शुमार यह किला, पीले बलुआ पत्थर से बना है और इसके चारों ओर कई भव्य द्वार हैं, जैसे गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हवा पोल। इन द्वारों को पार करते हुए आप दशहरा चौक नामक विशाल प्रांगण में पहुंचेंगे। किले के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, कैनन प्वाइंट, पांच-मंजिला मूर्तिकला महरवाल पैलेस और किला संग्रहालय जैसे कई आकर्षण हैं। नवंबर से मार्च तक का समय इस किले की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट होता है।

व्यास छतरी

बड़ा बाग में स्थित व्यास छतरी, जैसलमेर की शानदार विरासत का एक खास उदाहरण है। सुनहरे बलुआ पत्थर से निर्मित इन छतरियों की नक्काशीदार सुंदरता और राजस्थानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हर छतरी एक कहानी कहती है, राजपूत शौर्य और शिल्प कौशल की गवाही देती है। सूर्यास्त के समय, जब ये छतरियां सुनहरी रोशनी में नहा जाती हैं, तो नजरा और भी मनमोहक हो जाता है। एक ओर जैसलमेर किले का ऐतिहासिक दृश्य और दूसरी ओर रेत के टीलों का विस्तार, व्यास छतरी को एक स्पेशल एक्सपीरिएंस बनाते हैं। अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेस्ट होता है।

गड़ीसर झील

शहर के शोर-शराबे से दूर, जैसलमेर के बाहरी इलाके में स्थित गड़ीसर झील शांति और प्रकृति के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसा है। 14वीं शताब्दी में निर्मित, यह झील कभी पूरे शहर के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। आज, यह झील एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। आप यहां बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील के किनारे बने मंदिरों की शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर किले का मनमोहक दृश्य भी यहां से देखा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में यहां कई प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा होता है, जो नेचर लवर्स के लिए एक अलग ही एक्सपीरिएंस होता है। अक्टूबर से मार्च के बीच यहां घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।

खाबा किला

खाबा किला, जैसलमेर का एक अनोखा और रहस्यमयी स्मारक है, जो कुलधरा गांव के पास मौजूद है। बताया जाता है कि इस किले और गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन एक रहस्यमयी घटना के कारण वे एक रात अचानक गायब हो गए। ऐसे में, आज यह किला एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां आप न सिर्फ किले के खंडहरों का दीदार कर सकते हैं, बल्कि गांव के मनोरम दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। किले का संग्रहालय, इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है जो सदियों पुरानी कलाकृतियों से भरा हुआ है।

सैम सैंड ड्यून्स

सैम सैंड ड्यून्स का जादुई नजारा सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान और भी खूबसूरत हो जाता है। यहां आप रेगिस्तान के रेत के टीलों पर जीप सफारी कर सकते हैं, ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं, और रात को शांत रेगिस्तान में डेरा डाल सकते हैं। शाम को आप लोक नृत्यों और संगीत की धुन पर झूम सकते हैं, राजस्थानी व्यंजनों का लजीज स्वाद चख सकते हैं और यहां की रंगीन संस्कृति में खो सकते हैं।

सर्दियों में खाना बनाने में आता है आलस, तो इन बैच कुकिंग आइडियाज से आसान बनाएं अपना काम

सर्दियों में खाना बनाना एक बड़ा टाक्स लगता है क्योंकि इन दिनों ठंड की वजह से अक्सर आलस छाया रहता है। ऐसे में आप बैच कुकिंग की मदद से अपना काम आसान कर सकते हैं। यह कुकिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिससे काम को कम समय में झटपट किया जा सके। ऐसे में आज विंटर में कुकिंग के लिए इन बैच कुकिंग आइडियाज को ट्राई कर सकते हैं।

नई दिल्ली। सर्दियों का महीना शुरू हो चुका है। यह वह समय है जब सुबह बिस्तर से उठना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सुबह उठकर लंच बनाना इससे भी बड़ा टास्क लगता है। सर्दियों में अक्सर सुबह के समय उठने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर सुबह यह समझ नहीं आता कि लंच में आखिर क्या बनाया जाए। ऐसे में बैच कुकिंग आपके काम को आसान कर सकती है। कुकिंग करने के ऐसे कई तरीके हैं, जिससे कुकिंग आसान बनाया जाता है। इन्हीं में से एक है बैच कुकिंग। जब एकसाथ ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जाए, जिससे उसका कुछ हिस्सा हटा कर अगले समय के खाने के लिए रख दिया जाए, तो इसे बैच कुकिंग कहते हैं।

ये हेल्दी तो होता ही है, साथ ही ये सस्ता भी पड़ता है और इससे समय की बचत भी होती है। अकेले रहने वालों के लिए, व्यस्त लोगों के लिए या फिर हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए बैच कुकिंग एक बेहतरीन फूड हैक है। हालांकि, कुछ लोगों को इस बात की शंका जरूर हो सकती है क्या ये हेल्दी है। ये बाहर के खाने से सौ फीसदी हेल्दी है। कुछ वॉटर सॉल्युबल विटामिन इस दौरान नष्ट होते हैं लेकिन अधिकतर पोषक तत्व सीमित समय तक बरकरार रहते हैं। आइए जानते हैं बैच कुकिंग के कुछ आसान से आइडियाज-

स्प्राउट्स फ्रीज़ कर के रखें

इसे कभी भी सलाद, सब्जी, आलू के साथ ग्रेवी वाली करी या पुलाव में डाल कर बनाया जा सकता है। अगर घर में कोई हरी सब्जी नहीं है तो इसका उपयोग करें और ढेर सारी प्रोटीन और विटामिन के पोषण से भरपूर खाना खाएं।

इडली का बैटर

इडली का बैटर एक बैच में तैयार कर के स्टोर कर लें। ये फर्मेंटेड हेल्दी फूड का बेहतरीन विकल्प है जिसके बैटर से इडली के साथ डोसा और चीला भी बनाया जा सकता है।

करी बेस

तेल में जीरा का तड़का दे कर लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर को देर तक भून लें और इस करी बेस को फ्रिज में हफ्तों स्टोर करें। किसी भी सब्जी को बनाना है तो आवश्यकनुसार इस मसाले का बेस डालें और सब्जियां मिला कर मिनटों में सब्जी तैयार करें।

चटनी

हरी मिर्च, धनिया, लहसुन की चटनी, टमाटर और मूंगफली की चटनी, चना दाल और नारियल की चटनी या फिर सीज़नल फूड्स जैसे आंवला, कच्चा आम, पुदीना की चटनी बैच में बना कर स्टोर कर लें। ये भी हफ्तों चलती हैं। आप मात्र परांठे बनाएं और इन चटनी की वैरायटी का आनंद लें। झटपट स्वाद और पौष्टिकता के लिए चटनी से बेहतर विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता।

बिस्तर पर पेशाब करने वाले बच्चों के लिए कुछ घरेलू उपाय

नींद में बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और हो जाने के बाद ही उन्हें पता चलता है। इस कुछेक घरेलू उपाय आपके समक्ष है!"

दो अखरोट और दस किशमिश नियमित कुछ दिन बच्चों को खिलाने से बच्चे की बिस्तर पर पेशाब की आदर दूर हो जाती है।

सोते समय बच्चों को एक छोटा चम्मच शहद चटायें। रात को बच्चे के पैर हमेशा सामान्य पानी मे धोकर सुलाये।

बच्चों को सोने से पहले पेशाब जरुर कराएं ,रात में भी जब मौका मिले तो ये जरुर करें!!

पेशाब हो जाने पर डाटें - फटकारे नहीं ,प्यार से समझाएं! शाम के बाद तरल पदार्थ कम से कम दें!

दिमागी किसी वजह से बच्चा परेशान है तो स्वर्णमधु दे एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में मिलाकर दें!

इन छोटे प्रयासों को करने से सोते समय पिशाब करने की शिक़ायत से मुक्ति मिल जाएगी।

प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत आज

प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। शिवपुराण में वर्णित है कि, इस व्रत को रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवंबर 2024 में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा।

प्रदोष व्रत की तिथि

भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। नवंबर के महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को सुबह 6 बजकर 24 मिनट से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानि 29 नवंबर को सुबह 8 बजकर 40 मिनट तक रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पूजा का बड़ा महत्व है। शाम के समय में त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को ही है साथ ही उदया तिथि भी 28 को ही है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 28 नवंबर को ही रखा जाएगा।

प्रदोष व्रत का पूजा मूहूर्त

प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। 28 नवंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगा और रात्रि 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। इस दौरान भोलेनाथ की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।

प्रदोष व्रत की विधि

प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। तत्पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सुबह भगवान शिव की आरती करने के बाद आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दिन भर निराहार रहने के बाद शाम के समय भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए। 28 नवंबर के प्रदोष काल का शुभ पूजा मुहूर्त हम आपको ऊपर बता चुके हैं।

शाम को पूजा के दौरान आपको शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, शहद, धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर आपको भगवान शिव की पूजा शुरू करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ आप इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए। भोलेनात के मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का भी अगर आप इस दिन जप करते हैं तो उससे भी आपको शिव कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद आपको प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। अंत में आरती आपको करनी चाहिए। रात्रि के समय फलाहार करने के बाद, व्रत का पारण अगले दिन सुबह के समय आपको करना चाहिए।

प्रदोष व्रत का महत्व

प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और उनके पापों का नाश होता है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्त को सुख-शांति और समृद्धि जीवन में मिलती है। साथ ही अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और व्यक्ति दीर्घायु रहता है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और संतान सुख प्राप्त होता है।

प्रदोष व्रत के नियम

प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले स्नान करें और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें।

व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थाल की अच्छा से साफ सफाई करें और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। जल में कच्चा दूध, दही, शहद और गंगाजल मिलाकर अभिषेक करना है।

इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें।

पूजा के पाठ के बाद भोजन बनाकर सबसे पहले गाय को खिलाएं। इसके बाद खुद भोजन करके अपना उपवास खोलें।

दिल्ली को रानी खेड़ा इलाके में मिलेगा 147 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र, छह साल पहले परियोजना पर लगी थी रोक

सुषमा रानी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र दिया जाएगा। DSIIDC यहां पर मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करेगा। जनवरी तक प्लान के तैयार हो जाने की उम्मीद है। बता दें इससे पहले किसी कारणवश 14 दिसंबर 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस परियोजना को रोका था।

नई दिल्ली। आने वाले सालों में दिल्ली को रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) यहां मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करेगा।

सरकार ने इस योजना के लिए डीएसआईआईडीसी से विस्तृत प्लान बनाने के लिए कहा है। जनवरी तक प्लान तैयार हो जाने की उम्मीद है। किन्हीं कारणों से 14 दिसंबर 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने परियोजना को रोक दिया था।

एलजी भी इस योजना को दे चुके मंजूरी

इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 जुलाई को हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद से अब सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के मूड में है। एलजी भी इस योजना को मंजूरी दे चुके हैं।

इस औद्योगिक केंद्र में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके विकास के दौरान सभी मूलभूत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली और बाहर के लोग यहां उद्योग लगाने के लिए रियायती दरों पर जमीन ले सकेंगे।

सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

चूंकि यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक केंद्र होगा, इसलिए भूमि आवंटन में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसलिए, यह स्थान मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देगा।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि औद्योगिक हब विकसित करने का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और दिल्ली को विनिर्माण केंद्र में बदलना है। औद्योगिक हब में स्थापित होने वाले उद्योगों को प्रदूषण मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

एक स्मार्ट एकीकृत आईटी पार्क को होगा विकास

इसका विकास दो चरणों में किया जाएगा। यहां एक स्मार्ट एकीकृत आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें कई बिल्डिंग ब्लॉक शामिल होंगे जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होंगे। यहां आईटी, आईटीईएस, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, अनुसंधान और नवाचार हब जैसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

पिछले साल उस समय से सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीडीए से 147 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए एलजी भी इस परियोजना के लिए कुछ माह पहले जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं।

घर में सेंध लगाने के समान के साथ एक अपराधी पकड़ा गया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। पूर्वी जिला शाम लगभग 6 बजे, पीएस मयूर विहार के पुलिस कर्मियों ने स्थानीय निवासियों की मदद से, घर में चोरी / एयर कंडीशनिंग इकाइयों से तांबे के पाइप चोरी करने में शामिल एक आदतन अपराधी को पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान शैंकी उम्र 24 वर्ष, त्रिलोकपुरी के निवासी के रूप में हुई, जिसे पॉकेट 1, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली में चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता के अनुसार पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपी शैंकी ने मयूर विहार और आसपास के इलाकों में कई चोरियों में शामिल होने की बात कबूल की, जो उसके मादक द्रव्यों के सेवन की लत से प्रेरित था। आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह मयूर विहार में एक घर के बाहर एक एयर कंडीशनर से तांबे के पाइप चुरा रहा था। चोरी किए गए तांबे के पाइप के टुकड़े और पाइप काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, जिसमें एक हैकसॉ ब्लेड भी शामिल है, से भरा एक काला बैग उसके पास से बरामद किया गया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच जारी है।

लगभग 2 किलोग्राम वजन वाले एसी कॉपर वायर के तीन टुकड़े, साथ ही 1 बैग भी बरामद किया गया। चोर के पास से घर में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, जैसे स्क्रूड्राइवर, हैकसॉ ब्लेड, पाइप कटर, रिंच और स्क्रूड्राइवर बरामद किए गए।

आरक्षित पदों पर प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस नियुक्त किए जाने की टीचर्स एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजिज एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स एसोसिएशन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के 13 विभिन्न विभागों में एससी/एसटी व ओबीसी कोटे के खाली पड़े आरक्षित पदों पर प्रोफेसर ऑफ़ प्रेक्टिस के नये नियम के तहत प्रोफेसर लगाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे आरक्षित पदों को समाप्त करने की गहरी साजिश बताया है। टीचर्स एसोसिएशन ने बताया कि नियुक्ति के नये नियम प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस से केंद्रीय, राज्य व मानद विश्वविद्यालयों में भारत सरकार के आरक्षण नीति की सरेआम अवेहलना की जा रही है। एसोसिएशन ने इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है कि जिन विश्वविद्यालयों के विभागों में आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के पदों पर नियुक्ति होनी है उन पदों पर नियुक्ति के नये नियम लाकर प्रोफेसर ऑफ़ प्रेक्टिस के माध्यम से प्रोफेसर न लगाए जाएँ। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी विश्वविद्यालयों के लिए सर्कुलर जारी करना चाहिए ताकि आरक्षित पदों पर अनारक्षित श्रेणी के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के द्वारा नियुक्ति न की जाए इससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के पदों का नुकसान होता है।

टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ . हंसराज सुमन ने बताया है कि हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश) ने अपने यहाँ 13 विभिन्न विभागों जैसे- इंजीनियरिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्टरप्रोनशिप, कॉमर्स, सोशल साइंस, मीडिया, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, आर्म्ड फॉरसिस, लीगल प्रोफेशन, कम्यूनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि विभागों में पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। विभागों के द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के माध्यम से कितने पदों पर नियुक्ति की जानी है यह भी नहीं दर्शाया है । इन पदों को भरने की अंतिम तिथि 9 दिसम्बर 2024 है। विश्वविद्यालय के अनुसार इन पदों को भरने के लिए एकेडमिक काउंसिल की 31 जुलाई 2024 को हुई मीटिंग में निर्णय लेने के बाद 9 अगस्त 2024 को इसे कार्यकारी परिषद (ईसी) में अनुमोदित किया। उसके बाद ही प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के इन पदों को विज्ञापन के माध्यम से निकाला गया है। इन पदों की सम्पूर्ण जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट- Rac.lkouniv@gmail.com पर तय प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार इन पदों पर पार्ट टाइम व फुल टाइम नियुक्ति की जाएगी। पहले एक साल के लिए नियुक्ति दी जाएगी, उसके बाद यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, अधिक से अधिक तीन साल तक इसे बढ़ाने का नियम बनाया गया है उसके बाद आवश्यकतानुसार इसे पुनः एक साल और बढ़ाया जा सकता है।

टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों में यूजीसी की एक योजना के तहत प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के द्वारा प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। जबकि वे पद आरक्षित श्रेणी के

अभ्यर्थियों के थे । प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के नियम में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रखी गई है बल्कि उसके कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता के आधार पर चयन का नियम बनाया गया है। बता दें कि जिन विश्वविद्यालयों के विभागों में प्रोफेसर के पद एससी /एसटी व ओबीसी के बन रहे हैं उन्हीं पदों पर वहाँ के विश्वविद्यालय प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के तहत प्रोफेसरों की नियुक्ति कर रहे है। इन विश्वविद्यालयों में भारत सरकार की आरक्षण नीति की सरेआम अवहेलना की जा रही है। उनका कहना है कि यदि प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस की योजना को विश्वविद्यालयों में लागू करना है तो सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के लिए रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछले दो दशकों से एससी/एसटी व ओबीसी के शिक्षकों का शॉर्टफाल व बैकलॉग पदों को नहीं भरा गया है। अब उनके रिक्त पदों को भरने के लिए जब विज्ञापन दिए जा रहे हैं तो उन पर विश्वविद्यालय प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के नये नियम के तहत प्रोफेसर लगा रही है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2006 की रोस्टर और आरक्षण संबंधी गाइडलाइंस के बिलकुल विरुद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी गाइडलाइन --2006 के तहत ही विश्वविद्यालयों / शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण दिया था। लेकिन अब इन पदों को प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के द्वारा भरा जाएगा तो इन वर्गों का आरक्षण कैसे पूरा होगा ?

उन्होंने यूजीसी चेयरमैन से यह मांग की है कि वह सभी केंद्रीय, राज्य व मानद विश्वविद्यालयों के कुलपति / कुलसचिव को एक सर्कुलर जारी करे कि जब भी प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के तहत पदों का विज्ञापन निकालें, वह एससी /एसटी व ओबीसी कोटे के आरक्षण से अलग हो। यदि विश्वविद्यालयों को प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के पदों को निकालना है तो उसमें सभी वर्गों एससी/एसटी, ओबीसी व विकलांग कोटे के उम्मीदवारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही नियुक्ति करते समय शिक्षकों के रोस्टर का पालन किया जाए जिससे किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों को पदों की हानि न हो ।

दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी (डोमा) परिसंघ द्वारा प्रेस वार्ता

परिवहन विशेष न्यूज़

नई दिल्ली: डॉ उदित राज (पूर्व सांसद) राष्ट्रीय चेयरमैन, डोमा परिसंघ ने घोषणा किया कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी (डोमा) परिसंघ द्वारा 1 दिसंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है। अभी तक नागरिक समाज ईवीएम के खिलाफ मुखर होकर धरना-प्रदर्शन कर रहा था और राजनीतिक दल हां और न मध्य फसें हुए थे। 26 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने संशय की स्थिति तोड़ दी और ऐलान किया है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ईवीएम हटाने के लिए देश व्यापी आंदोलन करेंगे। डोमा परिसंघ ग़ैर राजनीतिक संगठन है लेकिन संविधान और लोक तंत्र को बचाने की बात जो करेगा, उसका समर्थन करेगा। 1 दिसंबर की रैली अगस्त माह से प्रायोजित है और यह इतिफ़ाक है कि ईवीएम हटाने की बात कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ़ से भी उठ गई है। लोक तंत्र आज़ादी से जीने की आत्मा है और अगर वह ख़त्म होता है तो प्रत्येक नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वह उठे और लड़े।

शाहिद अली, राष्ट्रीय महासचिव, डोमा परिसंघ ने कहा कि वक़्फ़ धार्मिक आज़ादी का हिस्सा है। संविधान की धारा 25 से 30 तक अल्पसंख्यक के अधिकार मौलिक अधिकार

के रूप में हैं। वक़्फ़ बिल ग़लत है। इसे वापिस किया जाए। अब केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित, ओबीसी, आदिवासी हमारे साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं । देश में झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक़्फ़ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है जो बिल्कुल ग़लत है। कुछ दल यह आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण का फल है जो बिल्कुल ग़लत है। 1921 में भारत में वक़्फ़ प्रॉपर्टीज का सर्वे किया गया था। जहां इस्लाम है वहां वक़्फ़ है तो कैसे यह कहा रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज अवैध हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी बहस करे, मैं सिद्ध कर दूँगा कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज पर अतिक्रमण हुआ है न कि वक़्फ़ बोर्ड ने किसी की प्रापर्टी पर किया है।

ओबीसी नेता सुरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि जाति जनगणना के बिना ओबीसी का उत्थान असंभव है। मंडल का विरोध किसने किया था? मंडल के ख़िलाफ़ किसने रथ यात्रा निकाला था? हम सब जानते हैं। जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? अब दलित, ओबीसी, माइनोरिटीज़ और आदिवासी मिलकर जाति जनगणना की माँग 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करेंगे। जो दल विरोध करेगा उसका ओबीसी बहिष्कार करेगा।

उपरोक्त कथन संविधान से संबंधित हैं और इसलिए हम कहते हैं संविधान खतरे में है।

डॉ उदित राज ने कहा हमारी अन्य मांगे पुरानी पेंशन बहाली, किसानों को एमएसपी की गारंटी, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़े, निजीकारण पर रोक लगे और यदि होता है तो उसमें आरक्षण हो, सबको समान शिक्षा मिले, धार्मिक आजादी हो, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण मिले, खाली पदों पर भर्ती हो, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, सरकारी धन से चल रही योजनाओं में आरक्षण मिले, भूमि आबंटन हो, आदिवासियों को जल-जंगल व जमीन से वंचित न किया जाए, आदि हैं।

प्रेस वार्ता में सतीश सांसी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, प्रो. रवि महिंद्रा, राष्ट्रीय महासचिव, विजय बहादुर यादव, उ.प्र. अध्यक्ष, सुरेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ नेता एवं मनोज यादव, उ.प्र.ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष भी उपस्थित थे ।j

केंद्र से केजरीवाल की बड़ी मांग... बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर क्या बोले?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्ण दास के साथ एकजुटता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके संत चिन्मय दास को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। आगे विस्तार से पढ़िए संत चिन्मय दास को लेकर पूरा अपडेट।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्ण दास के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है।

केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार से अपील करता हूं। इस मामले में हस्तक्षेप करके संत चिन्मय दास को जल्द से जल्द मुक्त कराएं।

केजरीवाल ने एक्स पर एक और पोस्ट डाली

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि दिल्ली में हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है। गली-मोहल्लों में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरे आम हत्याएं हो रही हैं। केजरीवाल ने कहा अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है।

नांगलोई में दो परिवारों से मिलने जाएंगे केजरीवाल

उन्होंने लिखा कि आज शाम को नांगलोई में ऐसे दो परिवारों से मिलने जा रहा हूं। एक परिवार की दुकान पर दिन-दहाड़े गोलियां चली थीं। दूसरे परिवार से फोन पर करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई और ये सब पूरी दिल्ली में हो रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में रोज अखबारों में खबरें छप रही हैं। क्या किसी ने ये सोचा था कि दिल्ली एक दिन देश का extortion Capital बन जाएगा?

दहशत में है दिल्ली के लोग

केजरीवाल ने लिखा कि ये सब अमित शाह के घर के कुछ किलोमीटर दूर ही हो रहा है। दिल्ली के लोग दहशत में जी रहे हैं और ये लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं।

भारत ने भी जताई नाराजगी

वहीं, बांग्लादेश में संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर भारत ने भी नाराजगी जताई है। भारत ने उनकी गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है।

सामने आया भारत के विदेश मंत्रालय का बयान

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। जारी बयान में चिन्मय दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही बांग्लादेश से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

वहीं, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगें पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं।" बता दें कि चिन्मय दास बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं।

संविधान दिवस पर व्याख्यानमाला का आयोजन

सुषमा रानी

डॉ. अम्बेडकर सोसायटी फॉर थाट्स एक्शन्स एण्ड कंसियसनेस (दस्तक) ने भारतीय संविधान दिवस, पर 5 वीं व्याख्यानमाला- ₹अनुच्छेद-21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा' का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता संजीव कुमार, पूर्व जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वक्ता वीरेन्द्र कुमार चौधरी, सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे व कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. इन्द्र मोहन कपाही, चांसलर नामिनी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने की।

संजीव कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 21 को मानवाधिकार का सबसे बड़ा रक्षक बताते हुए कहा कि इसअनुच्छेद में संविधान के सभी मौलिक अधिकार निहित हैं।

वीरेन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान जीवन जीने की सुरक्षा मिलती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यह अनुच्छेद सिर पर मैला

उठाने जैसे घृणित एवं अमानवीय कार्यों को कठोरता से रोकता है।

प्रो. इन्द्र मोहन कपाही ने संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान में समानता के भाव में बुद्ध के विचारों का प्रभाव है।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व त्रिशरण व पंचशील पाठ से हुआ, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया तथा कल्याण मंत्र व राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

दस्तक के अध्यक्ष डॉ . एन के संत ने अतिथियों का परिचय कराया, सचिव राजकुमार ने मंच संचालन व धन्यवाद उपाध्यक्ष विशु कोहली ने किया।

इस अवसर पर महासचिव मनोज कुमार सोलानी, कोषाध्यक्ष योगेश कुमार, प्रबंध समिति सदस्य दीपक इसरानी, एल.एस. हरित, कुमार गैरीसन, कुंती देवी, रेनू संगत, डॉ. अकांक्षा खुराना, सदस्य मंजू कुमारी, नीलम, कुसुम सोलानी, वीर सिंह, गुलाबसिंह सहित पत्रकार मनोज टंडन, सुभाष चंद व विद्यार्थी अध्यापक, आर डबल्यू एफ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली में बड़ा 'खेल' उजागर, दो अधिकारी बर्खास्त, कई का हुआ डिमोशन; स्कूल के बच्चों से जुड़ा है मामला

राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि के दुरुपयोग पर अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही कई कर्मचारियों का डिमोशन भी किया गया है। जांच में पता चला कि इन अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति से ब्याज कमाया है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एक बड़े खेल का मामला उजागर हुआ है।जांच में सामने आया कि अधिकारियों करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति से ब्याज कमाया है। अब इस मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है।

ये है मामला

दिल्ली में निगम स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि के दुरुपयोग पर निगमायुक्त अश्विनी कुमार ने सख्त कार्रवाई है। इसमें निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है तो कुछ कर्मचारियों का डिमोशन किया गया है।

मामला पूर्वकालिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य जोन का है, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया।

अधिकारियों ने ऐसे किया बड़ा खेल

निगम की ऑडिट रिपोर्ट में यहां मामला उजागर हुआ था, जहां जोन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों को दी जाने वाली राशि को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खाते खुलवाकर ट्रांसफर किया और फिर उस राशि से आने वाली ब्याज से मुनाफा कमाया। इस मामले की जांच चल रही थी।

प्रमोद व मंसाब जोशी को किया गया है बर्खास्त

जांच के बाद निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने निगम के शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक निरीक्षक प्रमोद व मंसाब जोशी को बर्खास्त किया गया है।

दो साल...एक हजार सोशल मीडिया पोस्ट, 40 हजार लोग परेशान; पर सड़क है कि बनती नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ईकोविलेज एक पंचशील हाइनिश व स्टेलर वन के मेन गेट से गुजरने वाली सड़क दो साल से बदहाल है। मुख्यमंत्री के प्रदेशभर में सड़कें गड्ढा मुक्त करने के आदेश के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। इससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री के प्रदेशभर में सड़कें गड्ढा मुक्त करने के आदेश के बाद भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ईकोविलेज एक, पंचशील हाइनिश व स्टेलर वन के मेन गेट से गुजरने वाली सड़क दो साल से बदहाल है। करीब दो महीने पहले प्राधिकरण द्वारा गिट्टी डलवा दी गई। उसके बाद सड़क का निर्माण नहीं कराया गया।

बदहाल सड़क से वाहनों के गुजरने के दौरान धूल उड़ने से प्रदूषण हो रहा है। सोसायटी के मेन गेट के सामने धूल उड़ने के कारण विद्यार्थियों व सोसायटी के लोगों के आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर गिट्टी पड़ी होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

धूल उड़ने से बच्चों, बुजुर्गों व सांस के मरीजों को को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोसायटी के लोगों का आरोप है कि कई ट्वीट करने व प्राधिकरण से शिकायत करने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है।

अधिकारी सड़क बनवाने की बजाय बना रहे बहाना

सोसायटी के लोगों का आरोप है कि दो साल से सड़क बदहाल है। प्राधिकरण के आला अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

शिकायत करने के बाद अधिकारी पहले चुनाव आचार संहिता के बाद सड़क बनवाने का आश्वासन देते रहे। उसके बाद वर्षा के बाद सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। अब ग्रेप 4 की पांबदियों की बात कह रहे हैं।सालों से सड़क बदहाल है। सड़क पर धूल उड़ने से बच्चों को स्कूल जाते व आते समय परेशानी होती है।

रंजना सूरी भारद्वाज

दो साल से सड़क बदहाल है। करीब दो महीने पहले गिट्टी डाली गई थी। उसके बाद सड़क नहीं बनाई जा रही है। बदहाल सड़क पर वाहनों के गुजरने के दौरान धूल उड़ने से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शशिभूषण शाह

प्रदूषण इस समय खराब स्तर पर है। उस पर उड़ती धूल के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। जल्द सड़क बनवानी चाहिए।

जीएस तिवारी

दो साल से सड़क बदहाल है। करीब एक हजार ट्वीट करने व प्राधिकरण अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सड़क नहीं बनाई जा रही है। ईकोविलेज एक, पंचशील हाइनिस व स्टेलर वन सोसायटी के मेन गेट से सड़क गुजरती है। तीन सोसायटियों में रहने वाले करीब 40 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़क पर धूल उड़ने के कारण विद्यार्थियों के आवागमन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है।

संजय शर्मा

प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिनभर वाहनों के आवागमन के दौरान धूल उड़ती रहती है। इससे काफी परेशानी हो रही है।

जीत बहादुर सिंह

ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हैं। अभी सभी निर्माण कार्य बंद हैं। पाबंदियां हटने के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

बाबा साहेब ने भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का मार्ग दिखाया : डॉ उमेश शर्मा चेयरमैन-उ.प्र.अपराध निरोधक समिति

हमें अपने संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए और इसे संजीदगी से समझकर इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए : डॉ उमेश शर्मा

आगरा,संजय साग़र सिंह। वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा चेयरमैन-उ.प्र.अपराध निरोधक समिति ने भारतीय संविधान दिवस और डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के महत्व पर बहुत सार्थक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, ₹संविधान दिवस का यह संदेश हमें यह समझाता है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का परिचायक है। यह संविधान हमारे राष्ट्र की एकता, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है और हमारे समाज में समावेशिता और समानता की स्थापना के लिए कार्य करता है।

श्री शर्मा ने आगे कहा, "बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को इस तरह से तैयार किया कि यह न केवल सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि यह हमें कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। उन्होंने भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का मार्ग दिखाया।

डॉ उमेश शर्मा ने संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह जरूरी है कि हम सभी अपने कर्तव्यों को समझें और संविधान का पालन करें, ताकि हम अपने अधिकारों का सम्मान कर सकें और समाज में समानता और न्याय स्थापित कर सकें। यह दिन हमें डॉ. अंबेडकर के योगदान को याद करने और संविधान के उद्देश्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है।

अंत में उन्होंने कहा, ₹हमारे संविधान में निहित सिद्धांत और निर्देश न केवल भारत के नागरिकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए और इसे संजीदगी से समझकर इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यीडा के विकास को मिलेगी रफ्तार, नोएडा के ये 15 गांवों में होगा तेजी से काम

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण के लिए बड़ी राहत देते हुए किसानों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से प्राधिकरण क्षेत्र के 13 गांवों की जमीन अधिग्रहण पर पड़ेगा असर। अब सड़कों से लेकर ढांचागत विकास में रुकावट काफी हद तक दूर हो जाएगी। आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों के आवंटियों को भी जल्द भूखंडों पर कब्जा मिल सकेगा।

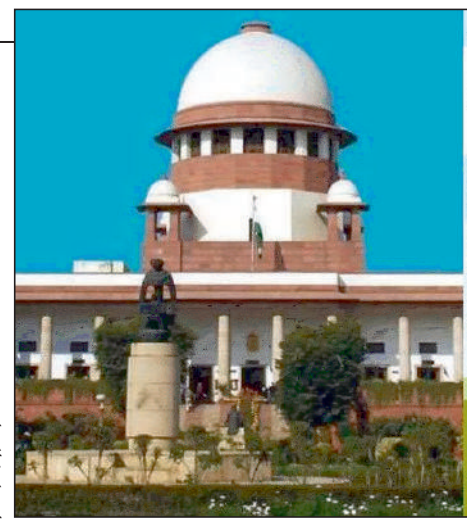

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) के रुके विकास को सुप्रीम कोर्ट ने गति दे दी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से प्राधिकरण के आवंटियों एवं ढांचागत विकास में रुकावट काफी हद तक दूर हो गई है।

इस फैसले का असर प्राधिकरण क्षेत्र के 13 गांव की जमीन अधिग्रहण पर पड़ेगा। किसान और प्राधिकरण के बीच जमीन अधिग्रहण का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण सड़कों से लेकर ढांचागत विकास में रुकावट आ रही थी।

29 गांवों की जमीन हो चुकी अधिगृहीत

यमुना प्राधिकरण 29 गांवों की जमीन अधिगृहीत कर चुका है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी हैं,जमीन की अड़चन को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने शासनादेश के माध्यम से किसानों को नो लिटिगेशन बोनस के तौर पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का वितरण का फैसला किया था, लेकिन सरकार की इस पहल के बावजूद प्राधिकरण के लिए जमीन की अड़चन पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई।

आवासीय सेक्टर 18, 20 औद्योगिक सेक्टर21,24, 24ए, 32, 33 के कई आवंटियों को एक दशक बाद भी भूखंडों पर कब्जे के लिए आज भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिन आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा मिल चुका है, वह भी सेक्टर में बसने की स्थिति में नहीं है। जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण जगह-जगह से सड़कों का निर्माण अधर में फंसा हुआ है।

यमुना प्राधिकरण कार्यालय।जागरण आर्काइव

सीवर, पेयजल पाइप लाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं। प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए अहम साठ मीटर चौड़ी सड़क व 120 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण भी जगह-जगह रुका हुआ है। साठ मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी।

वहीं 120 मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा की 130 मीटर चौड़ी सड़क को दनकौर क्षेत्र में जोड़ते हुए सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को जोड़ेगी। इस सड़क के किनारे आवासीय व औद्योगिक सेक्टर नियोजित हैं।

सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का शुरू होगा काम

इसमें लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग के सेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर 22 ई में प्रस्तावित अस्पताल व ट्रामा सेंटर के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। जमीन की अड़चन के कारण ट्रामा सेंटर का निर्माण कई साल से अटका हुआ है। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़ी 35 याचिका का निस्तारण करते हुए जमीन अधिग्रहण को सही ठहराया है। इसके साथ ही प्राधिकरण को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन जमीन अधिग्रहण से जुड़ी याचिका पर जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है।

प्राधिकरण के ओएसडी राजेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी। रुकी हुई परियोजनाओं को जमीन मिलने से उन्हें पूरा करना संभव होगा। आवंटियों को भूखंडों पर जल्द कब्जा मिल सकेगा।

इन गांवों में जमीन की अड़चन होगी दूर

कादलपुर, पचोकरा, रबूपुरा,चांदपुर, निलौनी शाहपुर, मिर्जापुर, रुस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, उस्मानपुर, अच्छेजा बुजुर्ग, धनौरी, रौनीजा।

इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ ही राज्यों और संघ के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत और नीति निर्देशक तत्व इन विशेषताओं में प्रमुख माने जाते हैं। भारतीय संविधान इमरजेंसी लाइट की तरह है। जब कभी हालात का घना अंधेरा देश के सामने उलझन जैसी स्थिति पैदा करते हैं, संविधान खुद-ब-खुद उजाला बन सामने हाजिर हो जाता है। संविधान के अंजोर में देश को सही राह दिख जाती है। आपातकाल जैसे एक-आध अपवादों को छोड़ दें तो पचहत्तर साल से यह संविधान हमारे लिए रोशनी की लकीर बना हुआ है। देश के सामने जब भी भटकाव जैसे हालात होते हैं, संविधान से ही आगे बढ़ने की राह निकल आती है।

भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहां दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चला जाएगा। लेकिन चर्चिल की इस चाहत को स्वाधीन भारत की मनीषा ओर लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के विकसित और बड़े माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी संवैधानिक व्यवस्था लागू होने या स्वाधीनता के तुरंत बाद समानता के आधार पर वयस्क मतदान का अधिकार नहीं मिला। लेकिन महज 18.33 प्रतिशत साक्षरता वाला देश लोकतंत्र की मजबूत राह पर चल पड़ा। ये सब उपलब्धियां अगर भारतीय लोकतंत्र को हासिल हुई हैं, तो इसकी मजबूत बुनियाद भारतीय संविधान ने रखी। लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद पर भारत राष्ट्र की जो मजबूत इमारत खड़ी हुई है, वह मजबूत संवैधानिक बुनियाद के बिना संभव नहीं हो सकता था।

इसी भारतीय संविधान ने 26 नवंबर के दिन 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। 64 लाख रूपए के कुल खर्च और दो साल 11 महीने 18 दिन तक चली बहसों के बाद इसी दिन 1949 में देश ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसके ठीक दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने इसे लागू किया और तब से यह हमारी लोकतांत्रिक राष्ट्र यात्रा की आत्मा, धड़कन, रक्त बना हुआ है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को हमने संविधान के निर्माता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन संविधान के निर्माण में 389 सदस्यों के साथ ही बीएन राव जैसे व्यक्तियों का योगदान कम नहीं रहा। भारत को आजादी देना जब तय हुआ, उसके पहले पंडित नेहरू की अगुआई में एक अंतरिम सरकार बनी। उसी अंतरिम सरकार के मुखिया के नाते जवाहरलाल नेहरू और उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कर्नाटक के जाने माने विधिवेत्ता बेनेगल नरसिम्ह राव यानी बीएन राव को विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त करके संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी। मद्रास और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े राव 1910 में भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए। साल 1939 में राव को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1944 में उन्हें

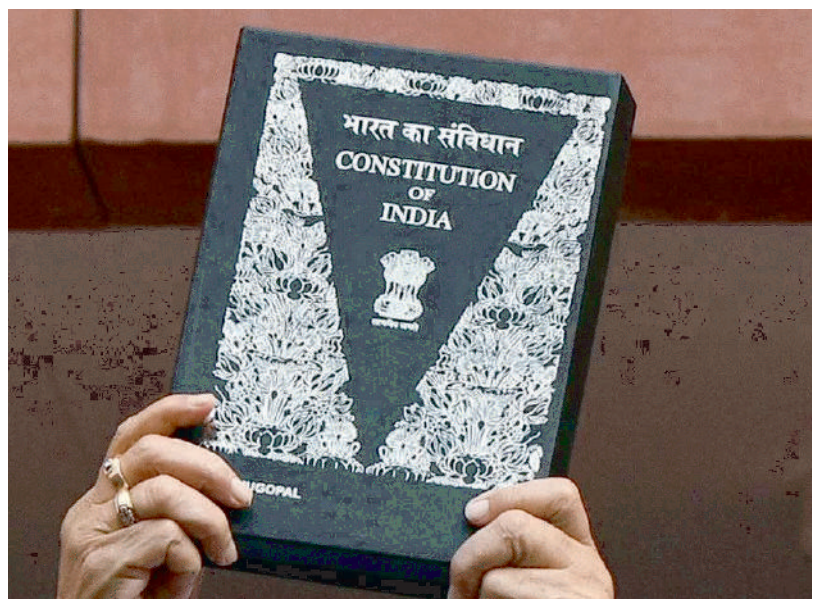

अपना प्रधानमंत्री बनाया। भारत सरकार के संविधान सलाहकार के नाते उन्होंने वर्ष 1945 से 1946 तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि की यात्रा की और तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 395 अनुच्छेद वाले संविधान का पहला प्रारूप तैयार करके संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. आंबेडकर को सौंप दिया।

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की बैठक में कहा गया कि संविधान सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार कर उसे संविधान सभा में पारित करने हेतु प्रेषित किया जाए। संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव आंबेडकर ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय बीएन राव को भी दिया है।

भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ ही राज्यों और संघ के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत और नीति निर्देशक तत्व इन विशेषताओं में प्रमुख माने जाते हैं। मूल अधिकारों की व्यवस्था के साथ ही कानून के सामने सभी नागरिकों के बराबर होने की बात भारतीय संविधान की ताकत है। भारतीय संविधान कठोर भी है तो लचीला भी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं। कुछ जानकार इसे संविधान की कमजोरी बताते हैं तो कई के अनुसार यह संविधान की ताकत है। इन संशोधनों के बहाने तर्क दिया जाता है कि अपना संविधान जड़ नहीं है।

चाहे अच्छाई का संदर्भ हो या कमजोरी का, पूरी तरह अच्छा या बुरा होने का विचार हकीकत नहीं हो सकता। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म, तीनों की मान्यता है कि पूर्णता का प्रतीक सिर्फ ईश्वर होता है, विचार या व्यक्ति नहीं। कुछ इसी अंदाज में भारतीय संविधान भी कुछ भारतीय विषयों को सही तरीके से चूक गया है। संविधान सभा की आखिरी बैठक के दिन संविधानसभा के सदस्य महावीर त्यागी ने सवाल पूछा था, 'अपने संविधान में कहां हैं गांधी जी, कहां है गांधी के विचार।' बेशक तब तक गांधी की हत्या हो चुकी थी, लेकिन गांधी के विचारों की तासीर तब तक आज की तुलना में कहीं ज्यादा महसूस की जा रही थी। भारतीय आजादी हर भारतीय के संघर्ष का नतीजा है, लेकिन गांधी की अगुआई, उनकी वैचारिक रोशनी और रचनात्मक कार्यों के बिना आजादी की कल्पना भी बेमानी है। दिलचस्प यह है कि संविधान में महावीर त्यागी को गांधी के इन रूपों के दर्शन नहीं हो पाए। दरअसल गांधी भारतीय संविधान में देश की मूल इकाई गांव को बनाना चाहते थे, व्यक्ति को नहीं। भारतीय परंपरा में व्यक्ति की महत्ता तो है, लेकिन वह सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति की सामाजिकता का बेहतर रूप ग्रामीण समाज है। लेकिन गांधी के इस विचार को नेहरू ने ही नहीं, अंबेडकर ने भी नकार दिया। नकारने को लेकर दोनों के शब्द बेशक अलग थे, लेकिन उनका बोध एक ही था। दोनों का मानना था कि सदियों से बजबजा रहे गांव भारतीय लोकतंत्र को राह नहीं दिखा सकते।

संविधान सभा में कई मुद्दों पर सदस्यों के बीच तीखी बहसें हुईं। आज जिसे हम लोकशाही या नौकरशाही कहते हैं, उसके अधिकारों को लेकर भी तीखी बहस हुई। दिलचस्प यह है कि संविधान सभा के कई सदस्यों को ब्यूरोक्रेसी को संवैधानिक अधिकार संपन्न बनाने पर एतराज था। उनका मानना था कि वे वैसा ही काम करेगी, जैसा अंग्रेजी सरकार के दौरान करती थी। एम ए अयंगार जैसे वरिष्ठ और माननीय सवाल ने नौकरशाही को वेतन और अधिकार की गारंटी देने पर सवाल उठाते हुए पूछा था था कि जब आम आदमी को रोटी और कपड़ा की गारंटी नहीं है, तो उन अधिकारियों को गारंटी क्यों दी जाए, जो विदेशी सत्ता की कठपुतली थी। तब पटेल ने अधिकारियों को ताकत देने का बचाव करते हुए तर्क दिया था कि एक बार अफसरशाही स्थापित हो जाएगी तो अधिकारी बदलाव के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारी बदलाव को राजी हुए, क्या वे लोकोन्मुख हुए, क्या उनका व्यवहार पुराने जमींदारों, रजवाड़ों या अंग्रेजों जैसा नहीं है? अपवादों को छोड़ दें तो कितने अधिकारी ऐसे हैं, जो खुद को आम लोगों जैसा मानते हैं और विशेषाधिकार नहीं चाहते?

भारत की भाषा समस्या का समुचित समाधान संविधान में नहीं दिखता। देसी होकर भी हिंदी अब भी दक्षिण और पूर्व के कुछ राज्यों के लिए स्वीकार्य नहीं बन पाई है और विदेशी अंग्रेजी इस देश की असल ताकतवर और राजभाषा बनी हुई है। हिंदी की जगह भारतीय भाषाओं की बात करने से हिंदी विरोध की आंच धीमी तो हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी की ताकत नहीं घटती। अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत राजभाषा हो, लेकिन नेहरू के दबदबे के चलते अपनी राय को मजबूती से रख नहीं पाए।

सोचिए, अगर भारत में व्यक्ति की जगह गांवों को राज्य की इकाई माना गया होता तो क्या होता? संवैधानिक उपबंधों के चलते गांव हमारे विकास प्रक्रिया और शासन की इकाई होते। तब आज का भारतीय परिदृश्य बदला हुआ होता। भारतीयता की सोंधी गमक के साथ अंदरूनी पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं काबू में रहतीं। अधिसंख्य जनसंख्या गांवों में ही रहती। शहरीकरण तेज नहीं होता और जनसांख्यिकी दबाव से शहरी ढांचा चरमरा नहीं रहा होता। इसी तरह अगर अफसरशाही को संवैधानिक गारंटी नहीं मिली होती तो बराबरी का भाव कहीं ज्यादा होता, तब अफसरशाही माने भ्रष्टाचार नहीं होता, तब हर रोग की जड़ी और इलाज अफसरशाही को ही नहीं माना जाता। समाज और व्यवस्था के सबसे बड़ी योग्यता अफसरशाही नहीं होती, तब सामाजिक परिदृश्य बदला होता। इसी तरह भाषाओं को लेकर आए दिन होने वाली लड़ाइयों की गुंजाइश नहीं होती।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

हापुड़ में निर्धारित रूटों पर ही चलेंगे ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार, 26 नवंबर को सीओ यातायात स्तुति सिंह सड़कों पर उतरीं और ई-रिक्शों को यूनिक नंबर आवंटित किए। पहले दिन 46 ई-रिक्शों को नंबर दिए गए। सीओ ने बताया कि प्रयास किए जा रहे हैं कि ई-रिक्शा चौराहों के आसपास न पहुंचे और अपने-अपने क्षेत्रों में ही सवारियों को उतारने छोड़ने का कार्य करें। इसके लिए चालकों के क्षेत्र के हिसाब से उन्हें यूनिक नंबर दिए जा रहे हैं।

हापुड़ शहर के तहसील चौपला, मेरठ तिराहा और दिल्ली रोड पर रामलीला मैदान के सामने इन ई-रिक्शों के कारण जाम के हालात रहते हैं और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

होंडा का 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) के अध्यक्ष, सीईओ और एमडी सुत्सुमु ओटानी ने बुधवार, 27 नवंबर को मीडिया को बताया, ₹पहले साल, हम दोनों इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों की लगभग 1 लाख इकाइयों के निर्माण की योजना बना रहे हैं।"

होंडा भारत में अपने चार कारखानों - मानेसर (हरियाणा), अलवर (राजस्थान), नरसापुरा (कर्नाटक) और विठलापुर (गुजरात) में सालाना लगभग 6.2 मिलियन दोपहिया वाहनों का निर्माण कर सकती है।

एक्टिवा ई और क्यूसी1 का निर्माण नरसापुरा फैक्ट्री में किया जाएगा। दोनों मॉडलों की कीमतें जनवरी में बताई जाएंगी और कंपनी की योजना फरवरी में दोनों मॉडलों की डिलीवरी शुरू करने की है।

स्थानीयकरण के बारे में पूछे जाने पर एचएमएसआई के बिक्री एवं विपणन निदेशक योगेश माथुर ने कहा, ₹हमने लगभग 99 प्रतिशत बैटरी का स्थानीयकरण कर दिया है तथा बैटरियां स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती हैं।"

एक्टिवा ई 6 किलोवाट डायरेक्ट ड्राइव मोटर पर बना है, जिसकी रेंज लगभग 102 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मॉडल बैटरी के साथ आता है जिसे इसके बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर पावर पैक एक्सचेंजर के द्वारा बदला जा सकता है।

होंडा पावर पैक एक्सचेंजर पहले से ही बेंगलुरु और दिल्ली में लाइव है और जल्द ही इसे मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि बेंगलुरु में करीब 88 स्टेशन हैं और मार्च 2026 तक करीब 500 ऐसे स्टेशन बनाने की योजना है। ये स्वैपिंग स्टेशन अन्य ओई एम के वाहनों के लिए भी सुलभ होंगे।

क्यूसी1 जो फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है। एक कॉम्पैक्ट इन-व्हील 1.8 किलोवाट मोटर पर बनाया गया है और इसमें 1.5 kWh लिथियम-आयन BP सेल केमिस्ट्री है। इसकी रेंज लगभग 80 किमी है और इसकी अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटा है

लोकप्रिय एक्टिवा स्कूटर और शाइन मोटरसाइकिल बनाने वाली यह कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। 2023-24 में इसने भारत में 45.30 लाख स्कूटर और मोटरसाइकिल बेचीं, जबकि इसने 3.63 लाख यूनिट निर्यात कीं।

शुरुआती चरण में ऑटोमेकर भारत में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए चरणबद्ध रोलआउट अपनाएगा और पहले वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार के 50% हिस्से को कवर करने का लक्ष्य रखेगा। प्रबंधन ने कहा कि फिलहाल भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात की कोई योजना नहीं है।

होंडा ने शुरुआत में एक्टिवा ई की बिक्री तीन महानगरों - बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में शुरू करने की योजना बनाई है। ऑटोमेकर के पास वर्तमान में रेड विंग डीलरशिप सहित देश भर में 6,000 से अधिक बिक्री और सेवा टचपॉइंट हैं।

माथुर ने कहा, ₹इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हमारी मौजूदा रेड विंग डीलरशिप के ज़रिए होगी। उनके पास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक समर्पित कोना होगा। हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से नेटवर्क बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं।"

बाधाओं के बावजूद कई कारणों से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य हैं उज्ज्वल

परिवहन विशेष न्यूज

उपभोक्ताओं की चाहत और जलवायु परिवर्तन को लेकर नए उत्साह के साथ भारत का खुदरा कार बाजार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और उसे प्रोत्साहित करने के नए चलन को अपना रहा है।

इसके दो कारण हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वास्तविक जागरूकता, जो वैसे समृद्ध उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है, जो पर्यावरण हितैषी वाहन खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं।

ईवी का रखरखाव सामान्यतः पारंपरिक वाहनों की तुलना में बहुत कम है, जो ग्राहकों के खर्च में कमी लाकर पसंदीदा विकल्प बन जाता है। ईवी पहले से ही अर्ध-स्वचालित है और निकट भविष्य में यह पूरी तरह स्वचालित होने वाला है। भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों को अपनाने और विनिर्माण ने ईवी अपनाने की प्रवृत्ति में इजाफा किया है। प्रोत्साहन आधारित सब्सिडी योजना ईवी अपनाने और उनके बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में परिवहन सुविधाओं को 30 फीसदी तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। यह वित्तीय प्रोत्साहन निर्माताओं और खरीदारों, दोनों की मदद करता है। फेम के दूसरे चरण में सरकार का लक्ष्य देश भर में 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। अब भी बहुत से भारतीय कार खरीदते वक्त इलेक्ट्रिक कार के प्रति संदेह में रहते हैं। सबसे बड़ी कमी बुनियादी ढांचे की है। फेम इस अंतर को पाटने का वादा करता है। किंतु भारतीय ऐसी चीजों में निवेश से हिचकते हैं, जो जल्दी उपलब्ध हो भी सकती है और नहीं भी। जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी को चुनने की संभावना कम है।

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के फलने-फूलने और बनाए रखने के लिए मजबूत सहयोगी तंत्र जरूरी है। यद्यपि कर छूट, प्रोत्साहन और पर्याप्त जागरूकता है। जलवायु कार्रवाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि देश के लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी ईवी को काफी हद तक बढ़ावा देने में मदद करती हैं। हालांकि बैटरी चार्जिंग मॉडल और ब्रांड पर भी निर्भर करता है। मुख्य बाधा बैटरी चार्जिंग में लगने वाले समय की है, जिसमें अभी नियमित रूप से घर में 8 से 12 घंटे लगते हैं। हालांकि नई तकनीकों और तेज चार्जर की वजह से चार्जिंग के समय में कमी आई है।

तमाम बाधाओं के बावजूद कई वजहों से भारत में ई-वाहन का भविष्य बेहतर है। तकनीकी प्रगति के साथ-साथ चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विस्तार और वित्तीय प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता ज्यादा से ज्यादा ईवी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है।

लगातार प्रचार-प्रसार व विज्ञापन एवं कर प्रोत्साहन जैसी सरकारी योजनाएं और सुलभ बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से भारत में ईवी को बढ़ावा देगा।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पिछली बार से ज्यादा ब्रांड होंगे शामिल, ईवी-ओनली ब्रांड रहेंगे मौजूद

परिवहन विशेष न्यूज

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को 17 से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें पहली बार की तुलना में ज्यादा ऑटोमेकर हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें इन कंपनियों के साथ ही Mercedes-Benz Audi और BMW जैसे ऑटोमेकर भी शामिल होंगे। इसे भारत मंडपम और द्वारका नई दिल्ली में नए यशोभूमि दो जगहों पर आयोजित किया जाएगा।

नई दिल्ली। जल्द ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो होने वाला है, जिसे पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था। इस बार इसे 17 से 22 जनवरी, 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में पहली बार की तुलना में ज्यादा ब्रांड हिस्सा लेने जा रहे हैं। 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें तकरीबन सभी कार निर्माता कंपनी के साथ कुछ लग्जरी कार निर्माता भी शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि Bharat Mobility Global Expo 2025 में कौन-सी कंपनियां शामिल होने जा रही है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कई कार और SUVs निर्माता कंपनी शामिल होने वाली है। इस लिस्ट में Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai, Mahindra, Tata Motors, Skoda and Volkswagen, Isuzu, Kia और JSW MG Motor India है। इन कंपनियों के साथ ही Mercedes-Benz, Audi और BMW जैसे ऑटोमेकर भी शामिल होंगे। इनके अलावा वियतनामी ईवी-ओनली ब्रांड Vinfast भी शामिल होगी, जो भारत में एंट्री के लिए प्लान बना रही है। इस शो में कंपनी अपनी 10 से 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेश करेगी। चीन की ल-ईवी ब्रांड, BYD भी अपनी कारों और SUVs को पेश करेगी।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शामिल होने वाली बाइक, स्कूटर कंपनियों की लिस्ट में Ather Energy, Bajaj Auto, BMW Motorrad, Honda Scooters, Hero Moto Corp, Yamaha India, Ola Electric, Suzuki Motorcycle India और TVS जैसे टू-व्हीलर ब्रांड शामिल है। यह टू-व्हीलर निर्माता इस शो में अपनी लाइन-अप को पेश करेंगे।

इस बार भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 होने के साथ ही एक कंपोनेंट शो भी होगा। इस कंपोनेंट शो को 18 से 21 जनवरी के बीच द्वारका नई दिल्ली में नए यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर) में आयोजित किया जाएगा। यहां पर भी कई कंपनियां अपने व्हीकल को शो करेंगी।

महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है सार्वजनिक परिवहन में "रेलबस"

परिवहन विशेष न्यूज

आने वाले वर्षों में बस और रेल दोनों सेवाओं में उल्लेखनीय बदलाव की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर बात की जाएँ तो रेलबसें न केवल जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जहां लोग सेवाओं, शिक्षा और काम तक आसानी से पहुंच सकने में सक्षम हैं।

भारत सरकार की परिवहन नीति में रेलबस के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में रेलबस की सेवाएं बड़ी भूमिका निभाएं। भारत सरकार को सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देते हुए रेलबस के लिए स्थायी परिवहन पदानुक्रम की शुरुआत करनी चाहिए।

रेलबस का एक प्रमुख लाभ मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे के साथ इसका निर्बाध एकीकरण है। नई रेल लाइनों के व्यापक और महंगे निर्माण की आवश्यकता के बजाय, रेलबसें मौजूदा सड़कों पर चल सकती हैं, जिससे स्थापित शहर लेआउट में व्यवधान कम हो सकता है। यह एकीकरण न केवल कार्यान्वयन के समय को कम करता है बल्कि बड़े पैमाने पर परिवहन सेवाओं को उन जगहों के करीब लाकर पहुंच भी बढ़ाता है जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं।

जैसे-जैसे दुनिया भर के शहर जनसंख्या वृद्धि, भीड़भाड़ और पर्यावरणीय गिरावट की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, रेलबस अधिक टिकाऊ और कुशल भविष्य के लिए आशा की किरण बनकर उभर रहा है। रेल नेटवर्क की दक्षता को बस प्रणालियों के लचीलेपन के साथ सहजता से मिश्रित करके, रेलबस आधुनिक शहरी परिवेश की जटिल गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए एक आकर्षक समाधान प्रदान करता है। जैसे-जैसे सरकारें और परिवहन अधिकारी नवीन जन परिवहन प्रणालियों में निवेश को तेजी से प्राथमिकता दे रहे हैं, रेलबस लोगों के शहरों के भीतर और उनके बीच आवाजाही के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे सभी के लिए गतिशीलता के एक नए युग की शुरुआत होगी।

रेलबस भविष्य में अगला सार्वजनिक परिवहन बनकर उभरेगी, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना रेलबस परिवहन के आने वाले युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह न केवल हरित ऊर्जा पर चलता है बल्कि लोगों की यात्रा को अधिक आसान और सुविधाजनक भी बनाता है। दुनिया के कई देशों ने इसे लागू करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसका दैनिक जीवन और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ईवीएक्सपो ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों मे शुरू किया प्रचार-प्रसार अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

ईवीएक्सपो के 'उत्कृष्टता के 10 वर्ष' पूरे होने पर न्यूगो इलेक्ट्रिक बस के द्वारा जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, शिमला व ऋषिकेश के बस पैनल के माध्यम से प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जा रहे हैं।

ईवीएक्सपो के संयोजक राजीव अरोड़ा का कहना हैं कि हमारा उद्देश्य हर निर्माता और ग्राहक को नज़र में लाना है ताकि वे ईवीएक्सपो मे आने वाले उत्पाद को अच्छी तरह से जान सकें। बसों के माध्यम से विज्ञापन दर्शकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है जहाँ वे कॉल-टू-एक्शन के माध्यम से आपके ब्रांड को और आगे बढ़ा सकते हैं। चूंकि ये सार्वजनिक परिवहन बसें पूरे शहर में चलती हैं, इसलिए विज्ञापनों को बहुत से लोग देख सकते हैं। हमारे इन माध्यम से जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, शिमला व ऋषिकेश के लोग बस ब्रांडिंग का सबसे अच्छा लाभ उठा पाएंगे।

पिछले दस सालों में भारत सरकार द्वारा बनाई गई ईवी नीति का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपना सकें।

इस प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शित पोस्टर में आप देखेंगे कि ऑल्टियस ऑटो सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित ईवीएक्सपो के टाइटल पार्टनरः खालसा ईवी, को-पावर्ड पार्टनरः ओलिव, एसोसिएट पार्टनरः सीवाई गोल्ड इंटरनेशनल के साथ ही एक्टिविटी पार्टनरः उड़ान, बैटरी और ड्राइवट्रेन पार्टनरः लिवगार्ड ड्राइवट्रेन, लैनयार्ड पार्टनरः टीएनआर, टू व्हीलर पार्टनरः मैक्सिम ईबाइक, लैनयार्ड पार्टनरः सफारी ई-रिक्शा, रजिस्ट्रेशन पार्टनरः रेज ग्लोबल एनर्जी, लैनयार्ड पार्टनरः एक्सेस टू पावर एक्सपी विद एक्स्ट्रा पावर, लैनयार्ड पार्टनरः ईस्टमैन, लाइटिंग पार्टनरः केके लाइट्स, पायनियर पार्टनरः स्पीगो-मोरनी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निर्यात होमोलोगेशन पार्टनरः एटीएसआईपीएल, नॉलेज पार्टनरः राजुलेक्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पार्टनरः सिटीलाइफ के अलावा आइकेट और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित और साथ ही ईवी ड्राइव द फ्यूचर मीडिया पार्टनर के रूप में दिखाई देंगे।

बचपन, परिवार और अनुभवों से सबक

विजय गर्ग

मेरे पिता अपनी जवानी के दिनों में गुस्सैल स्वभाव के थे। वह आमतौर पर रविवार की दोपहर को आराम करते और सोते थे। हमने बच्चों की तरह शांत रहने की कोशिश की। एक दिन, हम सामान्य से अधिक शोर-शराबे वाले रहे होंगे, और अंत में उसके द्वारा बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बाद में शाम को, मैंने अपने पिता के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखा। उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाने के लिए गंभीर रूप से माफ़ी मांगी। मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा. अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है.

अतीत हमारे वर्तमान को आकार देता है। भविष्य के लिए रास्ता बनाने के लिए वर्तमान अगले ही क्षण अतीत हो जाता है। हमारे पास यादें बची हैं जो हमें अमूल्य सबक भी सिखाती हैं

मैं भी अपनी उम्र के किसी भी अन्य युवा लड़के की तरह एक शरारती बच्चा था। जब भी मेरे माता-पिता मुझे डाँटना चाहते थे, तो मुझे अपनी दादी के पीछे छुपने के लिए एक आश्रय का आश्वासन दिया जाता था। फिर वह मेरे माता-पिता को अधिक दयालु होने की सलाह देती थी, साथ ही हमें अपने व्यवहार के बारे में विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहती थी।

मुझे बचपन की एक और याद याद आती है। हमारी स्कूल से घर वापसी उसी समय हुई जब मेरी माँ सो रही थी। हम दबे पाँव घर में घुसते थे, सावधान रहते थे कि उसे परेशान न करें। एक दोपहर मैं इतना उत्साहित था कि मैंने उसे जगाकर परीक्षाओं में अपने उत्कृष्ट परिणामों के बारे में बताया। फिर भी वह सुस्त थी, उसने अपनी नींद जारी रखने से पहले मुझे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। मैं अभी भी उसकी सहज प्रतिक्रिया को नहीं भूल सकता, भले ही मैंने उसे बहुत आवश्यक आराम में बाधा डाली थी।

मेरे पिता अपनी जवानी के दिनों में गुस्सैल स्वभाव के थे। वह आमतौर पर रविवार की दोपहर को आराम करते और सोते थे। हमने बच्चों की तरह शांत रहने की कोशिश की। एक दिन, हम सामान्य से अधिक शोर-शराबे वाले रहे होंगे, और अंत में उसके द्वारा बुरी तरह पिटाई कर दी गई। बाद में शाम को, मैंने अपने पिता के व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखा। उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाने के लिए गंभीर रूप से माफ़ी मांगी। मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा. अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है.

मुझे वह दिन याद है जब मैं उस युवा लड़की से मिला जो अगले कुछ महीनों में मेरी पत्नी और जीवन साथी बन गई। मुझे यह भी याद है कि शादी के रिसेप्शन के दौरान मेरी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। वे कठिन दिन थे जब हम एक साथ जीवन बिताने के गंभीर कार्य के लिए तैयार हो गए थे। हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं. जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने वाले ये दशक आसान नहीं रहे हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम कभी हार नहीं मानते। हम एक साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए सम्मान और स्थान की आवश्यकता की मान्यता है।

एक और पुरानी याद पुरी की बहुत पुरानी छुट्टियों की है। हमारा गेस्ट हाउस समुद्र तट से कुछ सौ मीटर की दूरी पर था। हमारी बेटियाँ बहुत छोटी थीं। मैं उनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए एक सुरक्षात्मक पिता था और रहूंगा। उस एक दिन, मैं बरामदे में बैठा, समुद्र तट पर खेल रहे दो बच्चों को प्यार से देख रहा था। मुझे उनकी खुशी पर गर्व था क्योंकि वे रेत से कुछ बनाते हुए खुशी से चिल्ला रहे थे।

मेरी माँ अपने प्रार्थना कक्ष में रामचरितमानस की एक प्रति रखती थीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि आप किसी भी समस्या का समाधान महाकाव्य से पा सकते हैं। आपको बस कोई भी पेज खोलना है, और शीर्ष पंक्ति आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के तरीके ढूंढने में मदद करेगी। मैंने भी कभी-कभी इसे आजमाया. मैंने सीखा कि जीवन की जटिल उलझनों से गुजरते हुए मैं हमेशा पारंपरिक सोच के माध्यम से स्थितियों से नहीं निपट सकता।

निष्पक्ष खेल, टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन करना, निष्पक्षता, टीम के सदस्यों को पूरा समय देना, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, सहानुभूति, टीम के लिए काम करना, टीम के सदस्यों के प्रदर्शन पर गर्व और आउट-ऑफ़-बॉक्स सोच, ये कुछ ही थे उन अमूल्य पाठों के बारे में जो मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया है।

मनोचिकित्सक, अब्राहम ट्वर्सकी के शब्द कई लोगों को पसंद आएंगे, "अतीत के बारे में चिंतन करने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अतीत से जो कुछ भी आप सीख सकते हैं सीखें, और फिर उसे अपने पीछे छोड़ दें। याद रखें, आप इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके पाठों का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाने होंगे सख्त कदम

उत्तर भारत सर्दी के साथ उच्च वायु प्रदूषण के एक और सीजन में पहुंच गया है। मध्य नवंबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से ऊपर पहुंच जाने के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने और निजी क्षेत्र के आधे कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम देने जैसे कई आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। भले ही वायु प्रदूषण की चर्चाओं के केंद्र में दिल्ली रहती हो, लेकिन यह उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण संकट है। पिछले सप्ताह कई उत्तर भारतीय शहरों ने बहुत खराब एयर क्वालिटी दर्ज की है। उच्च वायु प्रदूषण से बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को विशेष तौर पर खतरा है। इससे सांस संबंधी गंभीर संक्रमण और हृदय रोगों सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हर बार सर्दियां आते ही उत्तर भारत धुंध या स्मोग में क्यों घिर जाता है ? धुंध या स्मोग एक तरह का वायु प्रदूषण है, जो धुंए, कोहरे और अन्य प्रदूषकों का मिश्रण होता है। ऐसा इस क्षेत्र की खराब वायु गुणवत्ता के कारण होता है, जिसमें स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्त्रोतों से आने वाला प्रदूषण शामिल है। कच्चे रास्तों और निर्माण गतिविधियों की धूल, वाहनों और खुले में कूड़ा जलाने के धुएं जैसे स्थानीय स्त्रोत प्रदूषण बढ़ाते हैं। लेकिन सर्दी के महीनों में पराली जलाने जैसे कुछ मौसमी स्त्रोत और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने, हवा की रफ्तार घटने और तापमान गिरने जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हालात और भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए, वायु प्रदूषण के समाधान के लिए पूरे वर्ष ऐसे लक्षित कदम उठाने की जरूरत है, जो धुंध के मूल कारणों और इसके समाधानों पर केंद्रित हों।

सबसे पहले, उत्तर भारत के शहरों को धुंध वाले दिनों को घटाने के लिए पूर्वानुमान आधारित निवारक उपायों को अपनाना चाहिए। अब कई शहरों में अत्याधुनिक एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (एडीएसएस), जो पूर्वानुमान और माडलिंग के आंकड़ों का उपयोग करता हैं। काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) का आकलन है कि पूर्व सक्रियता के साथ लागू किए गए पूर्वानुमान आधारित आपातकालीन उपायों ने दिल्ली जैसे शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण वाले दिनों की संख्या घटाई है। अब ऐसे पूर्वानुमान अमृतसर, भिवानी, गुरुग्राम और पटना सहित 45 अन्य शहरों के लिए भी उपलब्ध हैं, ताकि प्रदूषण का उच्च स्तर सामने आने के बाद कदम उठाने की जगह पर पूर्व सक्रियता के साथ स्वच्छ वायु नियोजन किया जा सके। महाराष्ट्र के ठाणे जैसे कुछ शहर तो अवैध निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट फेंकने जैसे वायु प्रदूषण स्त्रोतों पर कार्रवाई करने के लिए एक्यूडीएसएस का उपयोग कर रहे हैं, जो शहरों में प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत है। उत्तर भारत के ज्यादा से ज्यादा शहरों को ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिए।

दूसरा, उत्तर भारत में किसानों को धान की पराली के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पराली जलने को लेकर दोषारोपण के बजाए इसके इन सीटू और एक्स - सीटू प्रबंधन विकल्पों के लिए, जमीनी सुविधाएं सुधारने पर ध्यान देने की जरूरत है। सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन के अनुसार, सरकारी प्रयासों ने पंजाब में पराली प्रबंधन मशीनों की उपलब्धता बढ़ाई है, और लगभग 58 प्रतिशत से अधिक किसानों ने इनका उपयोग करने की जानकारी दी है। किसानों को यह जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान पूरे वर्ष चलाना चाहिए कि पराली न जलाने के विकल्पों को अपनाने से उर्वरकों का खर्च और पानी का उपयोग घट सकता है और मिट्टी की सेहत सुधर सकती है।

तीसरा, सर्दियों में तापमान गिरने के साथ उत्तर भारत में शहरी प्राधिकरणों को पर्याप्त गर्म आश्रय स्थल बनाने की तैयारी करनी चाहिए और सुरक्षा गार्डों को हीटर उपलब्ध कराने का आदेश देना चाहिए। रात के समय काम करने वाले व्यक्ति और बेघर लोग अक्सर गर्मी के लिए बायोमास जलाते हैं, जिससे शहरी वायु प्रदूषण में आवधिक वृद्धि (अलग-अलग समय में वृद्धि होती है। चौथा, पूरे वर्ष प्रदूषण में योगदान देने वाले निर्माण और परिवहन जैसे स्त्रोतों को सुधारने के लिए प्रणालीगत सुधार लाना चाहिए। उदाहरण के लिए, निर्माण स्थलों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बारे में सिर्फ सर्दी के महीनों में ध्यान दिया जाता है। इस सीमित सक्रियता को बदलने की जरूरत है। परिवहन के मामले में, शहर मौजूदा मोबिलिटी पालिसी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने और सार्वजनिक परिवहन सहित इलेक्ट्रिक बसों बेड़े की दिशा में बदलाव तेज कर सकते हैं। इसके साथ, शहरों को सार्वजनिक परिवहन की लास्ट माइल कनेक्टिविटी, समयबद्धता और सेवा गुणवत्ता में सुधार लाते हुए इसके इस्तेमाल के लिए अधिक से अधिक यात्रियों को आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। अंत में, स्वच्छ वायु से जुड़े प्रयासों में नागरिकों को भी शामिल करना होगा।

विश्व कौशल के अनुरूप शिक्षा

विजय गर्ग

यह कहना एक सत्य है कि दुनिया एक जटिल समस्या बनती जा रही है और इससे निपटने के तरीकों को संरचित और समझने की आवश्यकता है। केवल यही बात दुनिया में मामलों के काम करने के तरीके पर बढ़ते दुख और घबराहट से बचाएगी। वित्त के क्षेत्र से एक उदाहरण स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। यह इंगित करना एक स्पष्ट बात है कि जीवित रहने के लिए सभी को वित्त की आवश्यकता होती और यदि कहीं से कमाया नहीं जाता है तो वित्त प्राप्त करना ही पड़ता है। वित्त या कमाई को समझने के इस व्यवसाय के लिए यह समझने की क्षमता की आवश्यकता होती है कि वित्त क्या है और इसे कैसे कमाया जा सकता है।

वित्त कई रूपों और रंगों में आता है। सभी वित्त में एक सामान्य कारक यह है कि यह किसी के प्रयास को मौद्रिक मूल्य देता है। और यह किसी सिस्टम को चालू रखने के लिए किए गए काम का प्रतिपूर्ति है। वित्त प्रयास और उसके प्रतिपूर्ति के बीच समीकरण निर्धारित करता है और वित्त बदले में खरीद और खरीद से परे जीवन की जरूरतों को प्राप्त करने दोनों के लिए एक उपकरण बन जाता है। ऐसा करने के लिए, किसी को मुद्रा, उसकी समतुल्यता और मुद्रा को प्रयास में कैसे मापा जाता है, यह समझने की आवश्यकता है।

यह हमारे प्रचलित स्कूल और कॉलेज प्रणाली की पहेली में से एक है कि इन मामलों को शायद ही कभी पाठ्यक्रम के माध्यम से या औपचारिक स्थिति में समझाया जाता है। वित्त के बारे में बहुत कुछ अवलोकन और घरेलू वातावरण के माध्यम से सीखा जाता है जिसमें कोई बड़ा हुआ है, जिसे परिचालन जीवन में लेन-देन में बदल दिया जाता है और किसी के जीवन में काफी पहले ही यह सीख लिया जाता है कि पैसे कमाने और इसलिए वित्त से निपटने के लिए उसके पास क्षमताएँ होनी चाहिए। प्रत्येक प्रणाली में प्रयासों और मुआवजे के बीच समतुल्यता के अपने तरीके होते हैं और इसे निर्धारित करने वाली शक्तियों को अक्सर बाजार की शक्तियाँ कहा जाता है। यह अपने आप में एक कला है जिसे जीवन कभी-कभी सरलता से और अक्सर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सिखाता है। इस प्रकार, यह है कि वित्त न केवल पेचीदा है, बल्कि यह समझने की ओर ले जाता है और फिर भी यह किसी के जीवन की आधारशिलाओं में से एक है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वित्त के कुछ बुनियादी घटक हैं जैसे कमाई, बचत, निवेश, मूर्त संपत्ति में परिवर्तित करना और बहुत कुछ। प्रत्येक क्षेत्र समय के साथ सीखने और वास्तव में किसी के अस्तित्व की खुशी या अन्यथा का एक विशेष क्षेत्र बन गया है। स्कूल की उच्च कक्षाओं में वित्त में कुछ ताकतें हैं जहाँ कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझाया जाता है और वित्त पर कुछ आवश्यक आधारभूत विचार साझा किए जाते हैं। जरूरत है इसे एक व्यावहारिक अभिविन्यास देने और फील्डवर्क के माध्यम से लोगों को वित्त के मूल्य और मानव जीवन में इसकी केंद्रीय भूमिका सिखाने की। अधिकांश कक्षाएँ सोच के उस चरण या उस तरह की सोच तक नहीं पहुँची हैं जिसका सीधा सा मतलब है कि अधिकांश लोग वित्त की अनिवार्यताओं और जीवन की नींव के बीच संबंध को समझे बिना ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर से स्नातक होता है और फिर जब तक कोई वित्त में कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं करता है, तब तक वह स्कूल में वित्त के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उससे आगे कभी कुछ नहीं सीख सकता है। यह एक नुकसान है क्योंकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्कूल में वित्त के बारे में जो पढ़ाया जाता है, वह वित्त के अभ्यास में बहुत दूर तक नहीं जाता है। हर किसी को यह जानने की जरूरत है कि कौशल और जानकारी को संभालने में

किसी के मूल्य और पर्यावरण द्वारा वित्तीय रूप से इसकी भरपाई कैसे की जाती है, के बीच संबंध क्या है यह अपने आप में एक पेचीदा प्रस्ताव है और जैसा कि पहले सुझाया गया है, इसके लिए फील्डवर्क की आवश्यकता है। फिर वित्त के अंतिम क्षेत्र हैं जिन्हें व्यावहारिक दुनिया से अवगत कराए बिना नहीं सीखा जा सकता है और यह ऐसा विषय नहीं है जिसे कक्षा में लाया जा सके। साथ ही, एक सामान्य शिक्षा प्रणाली में, फिर से अंतराल होते हैं जहां यह सीखना डिफॉल्ट रूप से होता है और लोगों को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से खुद के लिए भुगतान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे न केवल बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि कई तरह की जटिलताएं भी पैदा होती हैं। किसी को धोखा दिया जा सकता है या उसे यह नहीं पता हो सकता है कि कई मामलों में, किसी तरह के मुआवजे के बिना सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं और वह मुआवजा अक्सर पैसे के रूप में ही दिया जाता है। लोगों को पैसे, वित्त और प्रयास के बीच के संबंध को समझाना एक सार्थक दृष्टिकोण होगा।

ऐसा दृष्टिकोण न केवल स्कूलों बल्कि कॉलेजों के पाठ्यक्रम को भी सार्थक और व्यक्ति के अपने जीवन में अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद करेगा। जैसा कि मामला है, अगर कोई भौतिकी, रसायन विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल या किसी अन्य विषय में विशेषज्ञता हासिल करता है, तो उसे शायद ही यह एहसास हो कि तथाकथित विशेषज्ञता से परे, उसे एक सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है। यह सामान्य शिक्षा दूसरों के प्रति व्यवहार, स्वयं का प्रबंधन, आय को समझना, व्यय को समझना, बचत को समझना आदि हो सकती है। इसे सरल शब्दों में कहें तो वयस्कता प्रवेश करने और आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई बनने से पहले सीखने की सीमा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह सब परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हो रहा है, एक विधि को अपनाना; कुछ मामलों में काम करती है लेकिन अन्य में नहीं। औपचारिक इनपुट के माध्यम से वास्तविक जीवन में समायोजन के लिए खजाने को कम करने की स्पष्ट आवश्यकता है, इससे पहले कि कोई वयस्कता में स्नातक हो और खुले समुद्र में फेंक दिया जाए जैसे कि खुद की देखभाल करना।।

परीक्षा का समय? 10 तरीके जिनसे माता-पिता मदद कर सकते हैं

विजय गर्ग

कक्षा में अन्य प्रतिस्पर्धी बच्चों के साथ समानताएं बनाना आकर्षक हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि छवि केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए पोस्ट की गई है। यदि माता-पिता को सही तरीके से परामर्श दिया जाए, तो इससे उनके बच्चे के करियर में सकारात्मक तरीके से मदद मिलेगी। हालाँकि प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, मैं बच्चों और अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि वे चूहे की दौड़ में भाग न लें। मैंने कुछ संकेत एक साथ रखे हैं जो हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे और उनके माता-पिता के आत्मविश्वास में भी सुधार करेंगे। 1. अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति के बारे में खुद को अपडेट रखें चाहे आपका बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, प्रतियोगी या अन्य, यह महत्वपूर्ण है कि आप उससे नियमित रूप से बात करें कि वह अपनी पढ़ाई में कैसे प्रगति कर रहा है। यदि माता-पिता दोनों कामकाजी हैं, तो प्रत्येक माता-पिता दिन के अंत में बच्चे के साथ बारी-बारी से बैठ सकते हैं, यह जानने के लिए कि उसने दिन भर में कैसे मूल्य जोड़ा है और उसने क्या सीखा है। भले ही आपका बच्चा घर पर निजी कोचिंग ले रहा हो, कभी-कभी इसमें शामिल हों। ऐसा करने के लिए आप हर दिन कुछ मिनट अलग रख सकते हैं। उनके नियमित कार्यक्रम में खलल डालने की कोई जरूरत नहीं है. 2. अप्राप्य लक्ष्य निर्धारित न करें बच्चे अक्सर तनावग्रस्त रहते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य हासिल नहीं हो पाते। बुद्धिमत्ता, परिश्रम और अच्छे निर्णयों के साथ मिलकर सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करती है। यह भी याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है - कुछ स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। माता-पिता के लिए यह अपेक्षा करना अनुचित है कि हर बच्चा एक जैसा परिणाम देगा। 3. असफलता के बारे में बार-बार चर्चा न करें असफलता के डर के बारे में लगातार चर्चा करने से बच्चे को आघात पहुँच सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप कार चला रहे हों तो आपको सावधान रहना चाहिए लेकिन आप हमेशा दुर्घटना होने की चिंता नहीं कर सकते। इसी प्रकार, एक छात्र को असफलता और अस्वीकृति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय, आपको उससे इस तरह बात करनी चाहिए कि वह उसे अच्छे ग्रेड के साथ परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करे। 4. सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पर्याप्त नींद मिले बच्चों को प्रतिदिन कम से कम सात घंटे सोना चाहिए। जो छात्र दिन में लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं उन्हें रात में ब्रेक लेना चाहिए और पर्याप्त आराम करना चाहिए। अगर वे अपनी नींद कम कर देंगे तो इसका असर उनकी दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य पर पड़ने लगेगा। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए प्रकाश और अंधेरे दोनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक बच्चे को बढ़ने और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कड़ी मेहनत और आराम के निरंतर चक्र से गुजरना पड़ता है। 5. सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अच्छा खा रहा है माता-पिता होने के नाते, बच्चे के पोषण का उचित ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उसे वसा युक्त या ग़लत आहार देने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य और सामान्य दिनचर्या ख़राब हो सकती है। स्वस्थ और समय पर भोजन एक छात्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6. तुलना से बचें भारतीय माता-पिता के लिए कक्षा में अन्य प्रतिस्पर्धी बच्चों के साथ समानताएं बनाना आकर्षक हो सकता है। याद रखें, तुलना अपमान का सर्वोच्च रूप है। अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी न करें. यदि आप प्रेरित करने के लिए किसी उदाहरण का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसे स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने दें। अपने आप से पूछें: क्या आपका बच्चा कल की तुलना में आज बेहतर प्रदर्शन कर रहा है ? 7. सही संसाधन उपलब्ध कराएं माता-पिता के रूप में, आपको उपलब्ध

सर्वोत्तम और अद्यतन संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। यह गाइडबुक, प्रश्न बैंक या त्वरित नोट्स की सूची के रूप में हो सकता है। 8. परीक्षा से ठीक पहले मिलने-जुलने से बचें शादियों का मौसम आ गया है। हालाँकि, यदि आपका बेटा या बेटी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उस कार्यक्रम को छोड़ देना और माफी माँग लेना बुद्धिमानी होगी। जबकि ब्रेक लेना हैसलाह दी जाती है, एक पूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने से बच्चे की तैयारी की निरंतरता प्रभावित होगी। इसी तरह, माता-पिता रिश्तेदारों और दोस्तों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे उनसे मिलने न जाएं या लंबे समय तक वहां न रहें क्योंकि उनकी उपस्थिति से बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आप एक शेड्यूल बना सकते हैं जहां आप अपने बच्चे को मूवी देखने ले जा सकते हैं या रिफ्रेश और रीसेट करने के लिए किसी मॉल में जा सकते हैं। 9. कड़ी मेहनत को नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क को प्रोत्साहित करें माता-पिता के रूप में आप स्मार्ट स्टडी की अवधारणा को समझा सकते हैं और उसके अनुसार उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह रणनीति आपके बच्चे को तैयारी के सही अध्यायों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करके समय बचाने में मदद करेगी। 10. अपने बच्चे के साथ समय बिताएं बच्चों के लिए कई ट्यूशन और निजी कोचिंग में जाना असामान्य बात नहीं है, लेकिन माता-पिता को सप्ताह में दो बार कम से कम आधे घंटे के लिए बच्चे को बैठाकर पढ़ाना चाहिए। आप एक सरल अवधारणा समझा सकते हैं या बच्चे को उस समस्या का समाधान समझने में मदद कर सकते हैं जिससे वह जूझ रहा है। इससे उसे अत्यधिक मानसिक सहायता मिलेगी। माता-पिता अपने बच्चे को जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वह है उनका समय; दुर्भाग्य से, आधुनिक जीवन में यह दुर्लभ हो गया है। अपने बच्चे को सर्वोत्तम स्कूल में पढ़ाना और उन्हें सर्वोत्तम ट्यूशन/कोचिंग प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। माता-पिता के रूप में आपकी समय पर भागीदारी, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर न पड़े।

रिटायरमेंट के दिन ही c कर्मियों को मिल जाएगा पेंशन-भत्ता, लॉन्च हुआ ई-सर्विस बुक पोर्टल

परिवहन विशेष न्यूज

सीआईएसएफ में खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों में तैनात कर्मियों के सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते जारी करने और पेंशन शुरू करने में कई महीने लग जाते थे। विभाग ने उनकी सुविधा के लिए ई-सर्विस बुक पोर्टल तैयार किया है। वहीं सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने की सस्ती त्वरित एवं बाधारहित व्यवस्था के तौर पर ई-दाखिल पोर्टल की भी शुरुआत की है।

नई दिल्ली। सीआईएसएफ कर्मियों को अब सेवानिवृति के बाद पेंशन व अन्य भत्तों के लिए महीनों का इंतजार और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सीआईएसएफ ने रिटायरमेंट के दिन ही सभी भत्तों के भुगतान और पेंशन की शुरूआत के लिए ई-सर्विस बुक पोर्टल लांच किया है। सीआईएसएफ में 2400 से अधिक कर्मी हर साल सेवानिवृत होते हैं।

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया इनीशिएटिव के तहत सीआईएसएफ के कर्मियों के लिए ई-सर्विस बुक पोर्टल तैयार किया गया है। अन्य विभागों के लिए भी इसी तरह से ई-सर्विस बुक पोर्टल बनाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ में खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों में तैनात कर्मियों के सेवानिवृत्ति के बाद भत्ते जारी करने और पेंशन शुरू करने में कई महीने लग जाते थे।

विभिन्न विभागों में फिजिकल फाइलों के आने-जाने में समय तो लगता ही थी, गलती की भी आशंका बनी रहती थी। लेकिन ई-सर्विस बुक पोर्टल से सभी विभागों के बीच ई-फाइलों पर आदान-प्रदान आसानी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ सेवारत कर्मियों को भी मिलेगा। वे भी अपनी सर्विस बुक को आनलाइन देख सकेंगे और उनमें किसी भी गलती की स्थिति में समय रहते ठीक करा सकेंगे।

देशभर में कहीं से भी मिलेगा आपकी शिकायत का समाधान

सरकार ने बुधवार को कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने की सस्ती, त्वरित एवं बाधारहित व्यवस्था के तौर पर 'ई-दाखिल' पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकार 'ई-जागृति' पोर्टल लाने की दिशा में भी प्रयासरत है। यह पोर्टल मामला दर्ज करने, उनकी प्रगति की निगरानी एवं प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगा। इससे उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए परेशानी-मुक्त अनुभव सुनिश्चित होगा।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि लद्दाख में हाल ही में ई-दाखिल पोर्टल को पेश करने के साथ ही यह ऑनलाइन शिकायत प्लेटफार्म अब पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया है। पहली बार सात सितंबर, 2020 को पेश किए गए ई-दाखिल पोर्टल को उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विकसित किया गया है।

यह उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता अदालत तक पहुंचने के लिए एक कुशल और सुविधाजनक तरीका मुहैया कराता है। फिलहाल 2,81,024 यूजर ई-दाखिल पोर्टल पर पंजीकृत हैं और कुल 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 38,453 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

दिवालिया होने की कगार पर था एस्सार ग्रुप, शशि रुइया ने कैसे किया था कायाकल्प?

एस्सार ग्रुप के को-फाउंडर शशि रुइया का सोमवार को 81 साल की उम्र में देहांत हो गया। शशि रुइया ने अपने भाई रवि रुइया के साथ मिलकर 1969 में एस्सार ग्रुप की नींव रखी। एस्सार ग्रुप ने भारत के टेलिकॉम सेक्टर को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इसका कारोबार ऑयल से लेकर पोर्ट तक फैला हुआ है। आइए जानते हैं कि रुइया ने एस्सार को मुश्किलों से कैसे निकाला था।

नई दिल्ली। आपकी शख्सियत कितनी मजबूत है, इसका पता सफलता नहीं, बल्कि असफलता के दौर में चलता है। इस पैमाने पर एस्सार ग्रुप के फाउंडर शशि रुइया खरा सोना साबित हुए थे। रुइया का सोमवार को 81 साल की उम्र में देहांत हो गया। वह पहली पीढ़ी के कारोबारी थे और उन्होंने एस्सार ग्रुप की पहली नींव रखने से लेकर उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। इस दौरान कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन शशि ने हिम्मत नहीं हारी।

1969 में शुरू हुए छोटे से कंस्ट्रक्शन कारोबार से साम्राज्य में बदलने वाले एस्सार समूह का रेवेन्यू आज 1.18 लाख करोड़ रुपये है। ब्रिटेन में रिफाइनरी के साथ भारत, वियतनाम में हाइड्रोकार्बन भंडार व रिन्युएबल एनर्जी उद्यम हैं। इसका कारोबार 35 से अधिक देशों में फैला है। लेकिन, एक वक्त था, जब एस्सार ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था।

जब शशि को लगा कि सब खत्म हो गया

एस्सार ग्रुप एक वक्त काफी बड़ी वित्तीय मुश्किल में घिर गया था। स्टील की कीमतों में वैश्विक गिरावट और प्रोजेक्ट में देरी ने एस्सार ग्रुप को तबाह कर रखा था। उस पर बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। रुइया परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। हर किसी को लग रहा था कि अब एस्सार ग्रुप डूब जाएगा।

शशि ने एक इंटरव्यू में उस दौर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, 'मैं घर की छत पर बैठा चिंता में डूबा था। मुझे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। उसी वक्त मेरे छोटे भाई रवि वहां पर आएं। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं। हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमारी संपत्ति जो है, वो देनदारियों से अधिक है।'

एस्सार ग्रुप ने कैसे कर्ज खत्म किया?

शशि का कहना था कि उनके छोटे भाई की बातों ने उनके अंदर ऊर्जा का नया संचार किया। उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिला। शशि रुइया ने कर्ज चुकाने का रोडमैप बनाया और एस्सार ग्रुप की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने गुजरात स्थित तेल रिफाइनरी और उसकी कैप्टिव संपत्तियों को रूसी सरकार द्वारा नियंत्रित रोसनेफ्ट को बेचा। फिर इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क्स को बुकफील्ड को और कई अन्य होल्डिंग्स को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों को बेच दिया।

शशि रुइया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने बैंकों का सारा पैसा चुकाया। अपने परिवार का खोया रुतबा हासिल किया और कर्ज मुक्त एस्सार ग्रुप की नींव रखी। उन्होंने अच्छी संभावनाओं वाले बिजनेस को मजबूत किया और ज्यादा लागत वाले असेट को बेच दिया। 2022 में एस्सार के कर्ज मुक्त होने के बाद शशि के बेटे प्रशांत ने संदेश लिखा था... 'चुनौतीपूर्ण दौर का अंत। पीछे मुड़कर देखें तो, मैं अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से खुश हूं। साथ ही नए अध्याय की शुरुआत।'

सोने का बढ़ा भाव, चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

भू-राजनीतिक जोखिमों और डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ योजनाओं ने सोने में निवेश को बढ़ावा दिया। इससे सोने की कीमतो में दोबारा तेजी आई। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया। वहीं औद्योगिक और गहनों के लिए डिमांड बढ़ने से चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड तेजी आई है। आइए जानते हैं सोना और चांदी का लेटेस्ट प्राइस।

नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में दो दिन की गिरावट बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। मजबूत वैश्विक रुझानों और स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की ओर से खरीदारी के बीच सर्राफा कीमतों में भारी उछाल आया। चांदी 5,200 रुपये की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी के साथ 95,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 650 रुपये बढ़कर 78,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले दो सत्रों में पीली धातु में 2,250 रुपये की गिरावट आई थी। मंगलवार को यह 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

राष्ट्रीय राजधानी में दो सप्ताह के अंतराल के बाद चांदी में 5,200 रुपये की सबसे बड़ी एकदिन की उछाल देखी गई। इससे पहले, चांदी की कीमत में सबसे बड़ी उछाल 21 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, जब इसमें 5,000 रुपये की तेजी आई थी। पिछले दो दिनों में चांदी में 2,700 रुपये की गिरावट आई थी और मंगलवार के सत्र में यह 90,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

व्यापारियों ने कीमती धातु की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह मध्य पूर्व में अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ घरेलू बाजार में औद्योगिक और गहनों की बढ़ती खपत को दिया। एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 702 रुपये या 0.93 प्रतिशत बढ़कर 75,913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, "भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। सोने में व्यापक तेजी का रुझान बरकरार है, लेकिन अल्पकालिक अनिश्चितता बनी हुई है।"

दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी वायदा अनुबंध बुधवार को 280 रुपये या 0.32 प्रतिशत बढ़कर 88,530 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि पिछला बंद भाव 88,250 रुपये प्रति किलोग्राम था। वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स सोना वायदा 27 डॉलर प्रति औंस या 1.02 प्रतिशत बढ़कर 2,673.30 डॉलर प्रति औंस हो गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, "भू-राजनीतिक जोखिमों और डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ योजनाओं ने सोने में निवेश को बढ़ावा दिया। इससे सोने की कीमतो में दोबारा तेजी आई। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने भी सोने की कीमतों को समर्थन दिया।"

कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी-कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने कहा, "सोना 2,640 डॉलर प्रति औंस तक बढ़ गया है क्योंकि बाजार गुरुवार की थैंक्सगिविंग छुट्टी से पहले पीसीई मूल्य सूचकांक, तीसरी तिमाही के जीडीपी संशोधन और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों सहित प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा रिलीज पर ध्यान केंद्रित करता है।"

घटते जमा की चिंता छूटी पीछे, कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाने के लिए जोर बढ़ाएंगे सरकारी बैंक

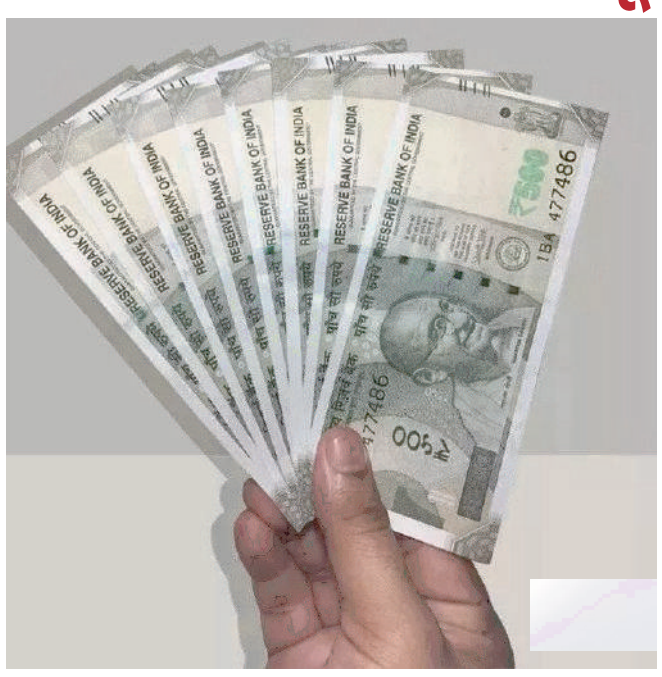

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार और आरबीआई पिछले काफी समय से बैंकों में घटते डिपॉजिट पर चिंता जता रहे थे। लेकिन केंद्र अब सरकारी बैंकों से लोन बांटने की रफ्तार तेज करने को कह रही है। सरकार के रुख में बदलाव के पीछे वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही तक के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर शंका के बादल घिरने को प्रमुख वजह बताया जा रहा है।

नई दिल्ली। अभी हाल तक आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक ने घरेलू बैंकिंग सेक्टर में जमा स्कीमों के तहत आने वाली राशि के मुकाबले बैंकों की तरफ से वितरित होने वाले कर्ज की दरों में वृद्धि की लगातार बनी स्थिति पर अपनी चिंता जता रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि कहीं बैंकों के सामने तरलता (फंड) की समस्या ना पैदा हो जाए।

लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार स्वयं बैंकों को ज्यादा कर्ज बांटने के लिए प्रोत्साहित करने लगी है। यह साफ नहीं है कि सरकार की मंशा में यह बदलाव घरेलू मांग में नरमी की स्थिति और हाल के दिनों में कई आर्थिक शोध एजेंसियों की तरफ से चालू वित्त वर्ष की तीसरी व चौथी तिमाही में विकास दर की संभावना घटाने की वजह से आया है या किसी और वजह से।

वित्तीय सेवा विभाग में सचिव एम नागराज ने जानकारी दी है, "हम ज्यादा से ज्यादा कर्ज की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक अगले तीन से चार महीनों में कई तरह के नये उत्पाद लांच करने वाले हैं जिससे हर सेक्टर में कर्ज की रफ्तार बढ़ेगी।" नागराज मंगलवार को सीआईआई की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि, "भारत में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इनमें कर्ज लेने की क्षमता भी है। इस क्षमता का उपयोग होना चाहिए। खास तौर पर फिनटेक सेक्टर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए कारोबार करने के माहौल को काफी आसान बनाया गया है। आगे भी कोशिश जारी है। उन्हें आसानी से वित्त सुविधा उपलब्ध कराने की भी पूरी कोशिश है।"

यह तो स्पष्ट नहीं है कि नये बैंकिंग उत्पाद किस किस्म के होंगे लेकिन बताया जा रहा है कि आम बजट 2024-25 में घोषित एक विशेष स्कीम का ही अगला चरण होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने पिछले आम बजट में बगैर पुराने वित्तीय रिकॉर्ड वाली आबादी को भी आसानी से बैंकों से सीमित मात्रा में कर्ज लेने की एक स्कीम की घोषणा की थी।

सरकार के रुख में बदलाव के पीछे वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही से चौथी तिमाही तक के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर शंका के बादल घिरने को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की आर्थिक विकास दर की संभावनाओं को 6.9 फीसद से घटा कर 6.7 फीसद कर दिया है।

इस बार त्योहारी सीजन में आटो बिक्री के आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि देश में मांग की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। ऐसे में सरकार कर्ज की रफ्तार बढ़ा कर मांग को भी हवा देने की कोशिश कर सकती है। उधर, 22 नवंबर, 2024 को आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में अभी तक कर्ज की रफ्तार 11.9 फीसद है जबकि बैंकों की जमा राशियों में 11.8 फीसद का इजाफा हुआ है।

अक्टूबर, 2024 के पहले पखवाड़े तक लगातार 30 महीनों तक कर्ज की वृद्धि की रफ्तार जमा की वृद्धि दर से ज्यादा रही है। इसके अलग-अलग कारण बताये गये हैं। कुछ अर्थविद इसे महंगाई तो कुछ अतिरिक्त बचत राशि के शेयर बाजार में लगाने को कारण बता रहे हैं। सितंबर, 2024 में बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में आरबीआई गवर्नर डॉ. दास की तरफ से जमा आकर्षित करने को लेकर ज्यादा कोशिश करने की सलाह दी गई है। बाद में यहीं बात वित्त मंत्री सीतारमण ने भी बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में दोहराई थी।

रॉकेट बने अदाणी ग्रुप के स्टॉक, किस वजह से आई तूफानी तेजी?

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्पष्टीकरण के बाद आई। इसके मुताबिक अदाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदाणी या अन्य अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट (FCPA) के तहत घूसखोरी और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उसने इस तरह के आरोप वाली सभी रिपोर्टों का खंडन किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।...

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के मालिकाना हक वाले अदाणी ग्रुप के अधिकतर शेयरों में बुधवार (27 नवंबर) को जोरदार तेजी देखने को मिली। अदाणी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों में से चार में अपर सर्किट लगा। अदाणी पावर और अदाणी टोटल गैस में 20-20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी की वजह

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्पष्टीकरण के बाद आई। इसके मुताबिक, अदाणी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदाणी या अन्य अधिकारियों के खिलाफ अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट (FCPA) के तहत घूसखोरी और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उसने इस तरह के आरोप वाली सभी रिपोर्टों का खंडन किया है।

कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर FCPA के तहत रिश्वतखोरी या विदेशी भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई आरोप नहीं है। कंपनी के मुताबिक, इनके खिलाफ सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से जुड़े आरोप लगे हैं।

अदाणी ग्रुप के किस शेयर में कितनी तेजी

अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्पष्टीकरण के बाद अदाणी ग्रुप के स्टॉक रॉकेट बन गए। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में 11.69 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,399 रुपये पर बंद हुए। वहीं, अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड का शेयर NSE पर 5.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,195.50 रुपये पर पहुंच गया। ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 10-10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। ये क्रमशः 988.40 रुपये और 660.80 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

अदाणी पावर के शेयरों में भी 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा। यह 525.15 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। अदाणी टोटल गैस के शेयरों में भी 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। यह 695.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

अदाणी ग्रुप के खिलाफ क्या है पूरा मामला?

21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने कहा था कि अदाणी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (करीब 2200 करोड़ रुपए) की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यह पूरा मामला अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है।

इन आरोपों में अदाणी ग्रुप के अधिकारियों पर सिक्योरिटीज में फ्रॉड और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अदाणी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में 21 नवंबर को करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये की घट गई थी। यह इसके इतिहास में किसी एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है।

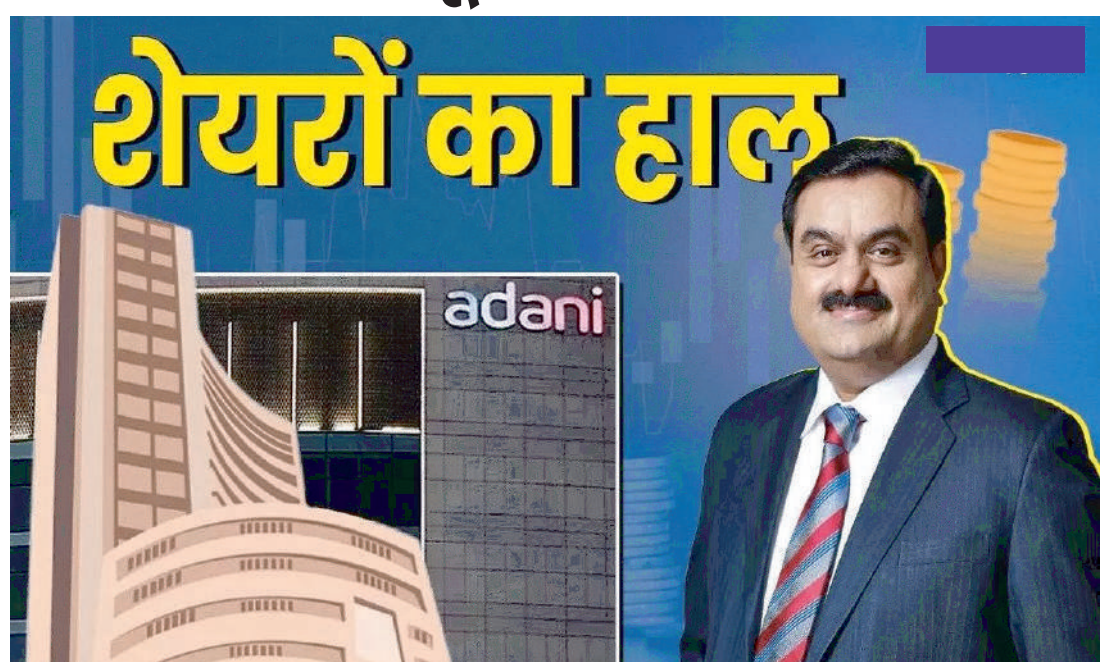

डिग्रीयां तो पढ़ाई के खर्चे की रसीदें है - ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

सृष्टि में अनमोल बौद्धिक ज्ञान का धनी मानवीय प्राणी को जन्म से ही परिवार, समाज, मानवीय संपर्कों से व्यवहारिक शिक्षा और ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है।याने जैसे जैसे मानुष बाल्य काल से बचपन और फिर युवा होता है, वैसे-वैसे व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ऑटोमेटिक अली स्वतः संज्ञान से उसकी बौद्धिक क्षमता परिपक्व होती जाती है और फिर स्कूल कॉलेज से लेकर अनेक डिग्रियों यानें किताबी ज्ञान पाकर सोने पर सुहागा की कहावत हम पूरी करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि, शिक्षा दो तरह की होती है। एक किताबी शिक्षा और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा। अगर किताबी शिक्षा के साथ साथ हमको व्याहारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की श्रेणी में आयेंगे। और अगर हमको शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी है तो हम शिक्षित लोगो की श्रेणी में आयेंगे।

साथियों भारत में कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कौशलता विकास पर जोरदार तरीके से फोकस किया जा रहा है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अलग से कौशलता विकास मंत्रालय का भी गठन किया गया है जो अनेक राज्यों में विभिन्न स्तरोंपर कौशलता विकास का जन जागरण अभियान चला रहा हैं। इसके लिए हुनर हाट सहित अनेकों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनका सबसे सटीक कारण हर नागरिक को नौकरी पाने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और जो कौशलता के रूप में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके किरदार में भी झलकेगा जो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति भी रही है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि किताबी पढ़ाई वाली डिग्रियां जिसे हम पढ़ाई के खर्चे की रसीदें भी कर सकते हैं, प्राप्त करने के बाद भी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। केवल डिग्री के बलपर हम अपने व्यवसाय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते या किसी जॉब में शामिल होने के बाद भी उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है और हमारा किरदार उसमें झलकता है कि हम इसके विशेषज्ञ हैं फ़िर भी अक्सर देखा गया है कि बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जब सेवा करनें का मौका आता है तो अनेक लोग विदेशों में जाकर सेवाएं प्रदान करते हैं और वही बस जाते हैं इसलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि डिग्रियां तो पढ़ाई की रसीदें हैं, परंतु ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके।

साथियों बात अगर हम किताबी ज्ञान की करें तो, परिभाषा के अनुसार जिसने किताबी ज्ञान अर्जित किया हो और स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को पास करके डिग्री हासिल की हो वो शिक्षित है, और जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, वो किताबी अनपढ़।पर क्या शिक्षा का अर्थ सिर्फ केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना ही है? एक शिक्षित इंसान के द्वारा फेंका हुआ कचरा, अगर सुबह एक किताबी अशिक्षित इंसान (सफाई कर्मचारी) उठाता है।ऐसे में किसे शिक्षित कहना चाहिए सफाई कर्मचारी को या कचरा फेंकने वाले को? आजकल की शिक्षा ऐसे ही रट्टा फिकेशन की शिक्षा होती जा रही है। जहाँ मतलब समझ आए या ना आए, बस रट्टा मारो और पास हो जाओ।

साथियों शायद इसीलिये किताबी पढ़े-लिखे अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया है पर शिक्षा की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ध्यान दे तो याद आता है जहाँ कुछ साल पहले ग्रेजुएशन ही काफी था, आज पोस्ट ग्रेजुएशन,क्या पीएचडी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तकनीकी शिक्षा पर जोर है। तकनीकी शिक्षा गलत नहीं है पर सिर्फ तकनीकी शिक्षा से काम नहीं चलेगा।

साथियों बात अगर हम किताबी शिक्षित और किताबी अनपढ़ व्यक्तियों की करें तो, बहुत अंतर है।किताबी अनपढ़ आदमी केलकुलेटर चलाना नहीं जानता सारा हिसाब किताब उंगलियों से करना पड़ता है पढ़ा-लिखा आदमी विना केलकुलेटर के चार में से दो घटाने के लिए भी अपनी उंगली नहीं घिसता। किताबी अनपढ़ व्यक्ति के पास अपने अनुभव के अतिरिक्त कुछ नहीं होता जबकि पढ़ा-लिखा व्यक्ति और के अनुभव भी उपयोग में ले आता है।किताबी अनपढ़ व्यक्ति अधिक प्रेक्टिकल होता है शिक्षित व्यक्ति इतनानही होता।कहीं बाहर जाने पर पढ़ा-लिखा व्यक्ति आसानी से पता ढूढ लेता है जबकि किताबी अनपढ को परेशानी होती है।एक युग था जब समाज में किताबी अनपढ बहुत थे तो उनका कामकाज भी उसी तरह चलता था ।आज किताबी अनपढ़ व्यक्ति को हर तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। उसे पढ़े-लिखे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है।

साथियों बात अगर हम संस्कारों और विचारधारा की करें तो व्यवहारिक शिक्षा और ज्ञान के परिपक्व व्यक्ति अपने कुल और माता पिता की विचारधारा पर चलकर संस्कारों का परिचय देते हैं। वहीं किताबी ज्ञान डिग्री लेने वाले कुछ अपवादों को छोड़कर संस्कारों और विचारधारा में साफ फर्क दिखा देने लगते हैं अपने कुल और माता पिता की विचारधारा पुरानी और ढकोसली लगने लगती है रिश्ते नातों में कमजोरी को बल मिलता है और विवाहित होने पर सिर्फ अपने परिवार की जवाबदारी तक सीमित हो जाते हैं जबकि व्यवहारिक ज्ञान के धनी व्यक्तियों में ऐसा नहीं है परंतु यह हम जरूर कहेंगे के किताबी ज्ञान वालों से अधिक ज्ञान समझ रखने वाले व्यवहारिक ज्ञान के धनी व्यक्तियों के दोनों हाथों में मलाई होती है जिससे स्थिति अनुसार प्रयोग में करते हैं स्थिति बिगड़ी तो तुम तो पढ़े लिखे हो!! हम ठहरे अनपढ़, हमको क्या समझता है!! और परिस्थिति का हमारे तरफ झुकाव रहा तो, देखो तुम तो पढ़े लिखे हो !तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? अच्छा हुआ हम तो अनपढ़ही बहुत अच्छे है।

साथियों बात अगर हम व्यवहारिक ज्ञान के महत्व की करें तो स्कूल में जब बच्चों से हाथ से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं तो बच्चे व उनके अभिभावक बहुत खुश होते है ।जब वे खुद कैंची से कागज काटते हैं तब व्यवहारिक ज्ञान आता है। हाथ से किया हुआ कार्य हम कभी नहीं भूलते और वही जीवन में काम आता है। किताब साइकिल चलाना नहीं सिखा सकती पर हमने एक बार चला ली तो जीवन भर नहीं भूलते। अच्छे अच्छे सांइस पढ़ाने वालों को यह नहीं पता होता कि एक लोहे के टुकड़े को कैसे पता चलता है कि उसके आसपास एक चुम्बक है और उसे उसी ओर जाना है? या चुम्बक को कैसे मालूम कि मुझे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचना है? यह टीचर नें व्यवहारिक ज्ञान से सिखाया। एक स्कूल में बच्चों से लगभग 600 प्रोजेक्ट बनवाए, हाथ से नमकीन मिक्सचर केक, बिस्कुट इत्यादि बनाना व बेचना। यह व्यवहारिक ज्ञान उनके जीवन में बहुत काम आएगा।व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप व्यवहारिक ज्ञान को विकसित कर सकते हैं: (1)अभ्यास करें: ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आपको नियमित अभ्यास के माध्यम से उसमें दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।(2) गुरु से सीखें: अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन लोगों से संपर्क करें जो आपके क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं।उनके मार्गदर्शन में आप अपने दक्षता को बढ़ा सकते हैं। (3) दूसरों के साथ अनुभव साझा करें: अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या समुदाय के अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करने से आप उनके अनुभव से भी सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। (4) समस्याओं का सामना करें: समस्याओं का सामना करने से आपको व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समस्याओं के समाधान के लिए अपने दिमाग को चुनौतियों के सामना करने की अनुमति दें। (5) पुस्तकें और संसाधनों का उपयोग करें: अपने विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकें, आर्टिकल्स वेबसाइट्स और वीडियोस का उपयोग करें। आजकल इंटरनेट पर भी अनेक विशेषज्ञ संसाधन उपलब्ध हैं। (6) अपने गलतियों से सीखें: कभी-कभी हम गलतियों करते हैं। इससे हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। गलतियों के माध्यम से आप अपने व्यवहारिक ज्ञान में सुधार कर सकते हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि, शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो हमारे मानवीय गुणों को भी विकसित करें। हमें संवेदनशील, सहनशील और व्यवहारिक के साथ-साथ देश और समाज के प्रति जागरूक भी बनाएं। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में होती थी।जहाँ ना सिर्फ पुस्तक ज्ञान सिखाते थे बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक और शस्त्र ज्ञान भी शिक्षा के साथ साथ ही सिखाया जाता था। अगर अच्छी किताबी शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा होने के बावजूद भी हम दकियानुसी सोच रखते हैं।अपने घर को साफ रखते हैं,पर सड़क पर कचरा करते है।दूसरो की पर्सनल लाईफ़ पर कमेंट करते हैं तो हमारे शिक्षित होने का क्या अर्थ है?इसलिए व्यवहारिक शिक्षा और ज्ञान में परिपक्व व्यक्तित्व का किरदार अगर किताबी ज्ञान की डिग्रियां ले तो सोने पर सुहागा होगा।

ओडिशा में जाति-जन गणना की मांग को लेकर सपा का धारना: मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: जाती-जनगणना के मुद्दे पर जहाँ समाजबादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं, वहीं इंडिया मेंट की सभी सहयोगी पार्टियाँ भी यही मांग कर रही हैं। लेकिन जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जिसने ओड़िशा में अपने चुनाव घोषणापत्र में मौजूदा आम चुनाव से पहले राज्य में जाति जनगणना कराने का वादा किया था, सत्ता में आनेके बाद पिछड़े वर्गों की गिनती करके 27% संवैधानिक संरक्षण मुद्दे से भाग रही है।

देश में अगले साल जनवरी से राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने जा रही है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सा वर्ग किस स्थिति में है।एक बार पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ज्ञात हो जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें आरक्षण योजना में उचित नीतिगत निर्णय ले सकेंगी। जाती जन-गणना के साथ पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मांगको लेकर समाजबादी पार्टी ओड़िशा के प्रदेश कमिटी ने मास्टर क्यान्तिन में धारना प्रदर्शन की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा1

समाजबादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव हाती यादव के नेतृत्व में, पार्टी प्रबक्ता प्रदीप मिश्रा, संपादक प्रताप किशोर बारीक़, उपाध्यक्ष देबेन्द्र कँहर, महामद अख्तर, के साथ सभी गैर-भाजपा राजनीतिक दलों के नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए और ओडिशा में जाति जनगणना कराने के पक्ष में तर्क पेश किये1

जाति जनगणना में ओबीसी या पिछड़ा वर्ग की भागीदारी अब एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश की कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 54% से अधिक है।पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, समाजबादी पार्टी ओडिशा राज्य समिति ने ओबीसी के लिए रोजगार के क्षेत्र में 11.25% के बजाय 27% की संख्या में आरक्षण के साथ मंडल आयोग की सिफ़ारिशों का लागू कराने की मांग की

अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए सरकार जाती-जनगणना कराए और प्रदेश की 54 फीसदी पिछड़ी जातियों को 27 फीसदी आरक्षण दे, नहीं तो समाजवादी पार्टी राज्यभापी समाजवादी जनजागृति अभियान के जरिए इसके खिलाफ जनआंदोलन करेगी। आने वाले दिनों में पार्टी इस मुद्देको लेकर सडक से संसद तक आंदोलन करेगी1

5 के रन फॉर गौ माता का टी-शर्ट और प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया

परिवहन विशेष

तेलंगाना. सिकंदराबाद स्थित मिनर्वा कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद में श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट और सर्वदलीय गौरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में 5 के रन फॉर गौ माता मैराथन दौड़ के टी शर्ट और प्रचार सामग्री का भाजपा/ RSS के वरिष्ठ नेता श्री मुरलीधर राव जी के नेतृत्व में हिंदू फ्रंट(छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन) के राष्ट्रीय कार्यालय में संपन्न हुआ ।

सर्वदलीय गौरक्षा मंच, राष्ट्रिय अध्यक्ष जयपाल सिंह नयाल सनातनी बताया कि इस कार्यक्रम में हिंदू धर्म गुरुओं और बड़ी संख्या में माताओं से भाग लिया । इस अवसर पर मंगलवार (हनुमान जी का वार) होने के पावन अवसर पर हिंदू हृदय सम्राट आज हिंदुओं की आवाज बन चुके पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के आदेश अनुसार जो लोग हिंदू एकता यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे है वे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करे और हमें भेजे का, आदेश मानते हुए सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और उत्तराखंड की माताओं द्वारा गौ माता के भजन भी गाए गए। जैसे कि सर्वविदित है आगामी 15 दिसम्बर 2024 को प्रातः 6 बजे से नेकलस रोड संजीवया पार्क से प्रारंभ होगी । इसमें सैकड़ों गौभक्त, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील IPS, IAS के साथ- साथ स्कूल के बच्चे तथा वाक में बुजुर्ग भी शामिल हो रहे है । इस के रन में अभी तक 10 महीने के बच्ची से लेकर 75 साल के बुजुर्गों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है ।आयोजकों का उद्देश्य उत्तराखंड,हिमाचल, महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात तेलंगाना उत्तर प्रदेश माध्य प्रदेश की तर्ज पर केंद्र और राज्य सरकारों से गौमाता को राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दिलाना है । और राष्ट्रीय स्तर पर गौवंश आधारित खेती से जैविक खेती का प्रचार-प्रसार करना , A 2 दूध यानी देशी गाय के दूध का प्रचार करना है । ताकि खतरनाक कैमिकल युक्त फटीलाइजर से आज कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम हो सके।आज देश भर में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे संत महात्मा शंकराचार्य तक पद यात्रा कर रहे है उन्हीं के मार्गदर्शन पर और गौ माता के प्रचार हेतु यह पवित्र कार्यक्रम हैदराबाद में भी किया जा रहा है । हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहां है हर एक भारतीय साल में 250 ग्राम यूरिया आज के अनाज के माध्यम से खा जा रहा है इससे बचने के लिए जैविक खेती गौ आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए मारकाट कब थमेगी?

भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

संभल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' को कैसे समझा जाता है। संभल की ज़िला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मौतें हुईं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।

संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया- 'मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदल दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस

बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहाँ कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।' मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर ज़ोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक़ जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है।

याचिकाकर्ताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दावा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालाँकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर रोक लगाती है। धारा 4 में कहा गया है कि उस तिथि को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन के सम्बंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त (समाप्त) कर दी जाती है, जिससे ऐसे रूपांतरणों के सम्बंध में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के समय पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला, जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन को जटिल बना दिया है।

न्यायालयों ने इन टाइटल मुकदमों को कैसे अनुमति दी है? पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अदालतों ने ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों से सम्बंधित टाइटल मुकदमों को बनाए रखने योग्य क़रार देकर अनुमति दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी ने संकेत दिया कि अधिनियम के तहत किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति को बदलना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके ऐतिहासिक चरित्र की जांच अभी भी अनुमेय हो सकती है। इस व्याख्या ने ज़िला न्यायालयों को अधिनियम की मंशा का सीधे उल्लंघन किए बिना ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का आधार प्रदान किया है। संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस एकपक्षीय निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों के जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

मुस्लिम लीग के पांच सांसद सांसद जा रहे थे संभल, हापुड़ पुलिस ने छिजारसी टोल से लौटाया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल आने की सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच केरल के पांच सांसदों को छिजारसी टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। लगभग आधे घंटे तक चली वार्ता के बाद उन्हें वापस भेज दिया। संभल की जामा मस्जिद में मंदिर का दावा करने के बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद वहां हिंसा हो गई।

हापुड़। पिलखुवा के छिजारसी टोल प्लाजा पर सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के संभल जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन दूसरे दिन भी अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान अधिकारियों ने केरल के पांच सांसदों को छिजारसी टोल प्लाजा पर रोक लिया। लगभग आधा घंटा चली सांसदों व अधिकारियों की वार्ता के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। पिछले दो दिनों से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के संभल जाने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिल रही थी। जिस पर दो दिनों से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी छिजारसी टोल प्लाजा पर डेरा डाले हुए है। इसी कड़ी में बुधवार की दोपहर दो कार सवार केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद पीवी अब्दुल बहाव, हैरिस बीरन और सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, एकेए अब्दुल समद, नवास गनी संभल जाने के छिजारसी टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्हें हापुड़ पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वो संभल जाकर माहौल को परखेंगे। इसके बाद सांसदों व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की सड़क किनारे लगभग आधा घंटा वार्ता हुई। इसके बाद सभी सांसद वापस लौट गए। वहीं, राहुल व प्रियंका के लिए पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023